सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 188, नई दिल्ली, सोमवार 15 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हार तो हर कोई मान लेता है, ये सबसे आसान तरीका है, जीतता वही है जो अंत तक लड़ता है।

03 पीएम मोदी ने कहा था, "ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन क्रिकेट...
06 भौतिकी से पहले, गणित था: मानव इतिहास के माध्यम से यात्रा
08 रक्त कैंसर रोगियों के जीवन से खिलवाड़: एससीबी ने 'असिमिनीब परीक्षण' बंद किया

क्या भारत देश के प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जनता को यह देंगे जो वह जनता के मतों से जीते प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाते हैं?

संजय बाटला

क्या आप सभी को लगता है की आम आदमी जो 20000 से 30000 रूपये महीना कमाता है वो गरीब नहीं हैं और जो खास व्यक्ति जिसकी आमदनी/ तनख्वाह 1,50,000 रूपये महीना से अधिक है और वह भी इनकम टैक्स माफ के साथ वह इस सुविधा का पात्र है जो आपने उनके लिए उपलब्ध करवा रखी है

माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवम् सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन, जनता को दी जाने वाली फ्री की सभी योजनाओं को बंद कर के जनता को सिर्फ सांसद भवन जैसी कैन्टीन हर दस किलोमीटर पर खुलवा दीजिए,

1. 29 रूपये में भरपेट खाना मिलेगा, 80% लोगों को घर चलाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी ना सिलेंडर पर सब्सिडी की जरूरत और ना ही राशन पर। जिससे चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियां रहेगी और सभी कहेंगे सबका साथ सबका विकास ।

इस पर गौर करें :- शान है या छलावा

पूरे भारत में एक ही जगह ऐसी है जहाँ खाने की चीजें सबसे सस्ती है ।

1. चाय = 1.00
2. सुप = 5.50
3. दाल= 1.50
4. खाना =2.00
5. चपाती =1.00
6. चिकन= 24.50
7. डोसा = 4.00
8. बिरयानी=8.00
9. मच्छी= 13.00

इन कीमतों पर यह सभी प्रकार के व्यंजन/ खाना सरकार द्वारा गरीबों के उपलब्ध करवाना चाहिए पर यह सब उपलब्ध है भारतीय पार्लियामेंट कैंटीन में वह भी सिर्फ जनता द्वारा अपने मतों से जीता कार भेजे गए प्रतिनिधियों के लिए, यह सुविधा जो आपने उपलब्ध करवा रखी है वहां किसी की भी आमदनी/ तनख्वाह 1,50,000 रूपये महीना से कम नहीं है और वह भी इनकम टैक्स माफ के साथ।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी की सड़क हादसे में मौत
पत्नी की हालत भी नाजुक, बाइक को BMW ने मारी थी टक्कर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के व्यस्त धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर हुए एक सड़क हादसे में भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से हरि नगर स्थित अपने घर वापस जा रहे थे, तभी एक BMW कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह और उनकी पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों को न्यूलाइफ हॉस्पिटल, जीटीबी नगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नवजोत को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है और उनका इलाज जारी है. हादसे में आरोपी महिला चालक और उसके पति भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दिल्ली पुलिस ने BMW कार को जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. कार सवार दंपति गुरुग्राम के रहने वाले हैं.

पुलिस के अनुसार, आज दोपहर में दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन को धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन की ओर ट्रैफिक जाम की शिकायत पर तीन पीसीआर कॉल प्राप्त हुईं. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक bmw कार सड़क पर तिरछी खड़ी थी, जबकि एक मोटरसाइकिल डिवाइडर के पास मेट्रो पिलर नंबर 57 के निकट पड़ी मिली. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस बीएमडब्ल्यू ने

नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारी उसे एक महिला चला रही थी.

राहगीरों ने एक टैक्सी बुक करके गंभीर रूप से घायल नवजोत और उनकी पत्नी को जीटीबी नगर स्थित अस्पताल भेजा. बाद में पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि नवजोत की मृत्यु हो गई है, जबकि उनकी पत्नी की हालत भी गंभीर बनी हुई है. हादसे की जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (fsl) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

साउथ-वेस्ट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) ने कहा, 'हमें पीसीआर कॉल मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई. वाहन को जब्त कर लिया गया है और आरोपी दंपति के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. हम सख्त कानूनी कदम उठाएंगे.' पुलिस ने हिट एंड रन के तहत आईपीसी की धारा 304A (लापरवाही से मौत) और मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है।

महानदी कोल फिल्ड्स में निम्नस्तरीय कोयला खरीद कर हाई ग्रेड कोयला उठाने के चल रहे घोटाले पर प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री का ध्यान आकर्षण

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली - उफ्तत्सा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) की ओर से, जो देशभर के ट्रक ट्रांसपोर्टरों, ड्राइवरों और सारथियों के हितों की रक्षा करने वाला एक मात्र प्रमुख संगठन है, ने महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में चल रहे कथित कोयला घोटाले की ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी का ध्यान आकर्षित किया है1 यह घोटाला न केवल राष्ट्रीय संसाधनों की लूट है, बल्कि ट्रक ट्रांसपोर्टरों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इससे कोयला परिवहन में अनियमितताएं बढ़ रही हैं, अवैध व्यापार फल-फूल रहा है और ईमानदार ट्रांसपोर्टरों व ट्रक मालिकों को नुकसान हो रहा है।

घोटाले की तथ्यात्मक जानकारी एवं घटनाक्रम के तहत महानदी कोल फिल्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और ओडिशा में संचालित है, में हाल के वर्षों में कोयला ग्रेड से संबंधित अनियमितताओं की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इस घोटाले में मुख्य रूप से सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, छेंदीपदा और तालचेर क्षेत्र शामिल हैं, जहां अवैध खनन, रिश्वतखोरी, पर्यावरणीय उल्लंघन, भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी और निम्न ग्रेड कोयला को उच्च ग्रेड के रूप में उठाने की प्रथा व्याप्त है। हालांकि, इस विशिष्ट घोटाले पर सीधे आधिकारिक जांच रिपोर्ट्स भी सोशियल मिडिया पर व्याप्त हैं, लेकिन समान प्रकृति के मामलों से प्रेरित होकर यह स्पष्ट है कि निम्नस्तरीय (लो ग्रेड) कोयला को हाई ग्रेड के रूप में उठाने/बेचने की प्रथा देश के कोयला क्षेत्र में व्याप्त है। नीचे उपलब्ध तथ्यों एवं घटनाक्रम पर आधारित जानकारी दी जा रही है, जिसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, छेंदीपदा और तालचेर के घटनाक्रम को जोड़ा गया है:

पृष्ठभूमि एवं प्रारंभिक घटनाक्रम (2012-2024)- देश के कोयला आयात एवं वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी गईं, जहां इंडोनेशिया जैसे देशों से सस्ता, निम्न कैलोरी वैल्यू (लगभग 3,500 किलोकैलोरी/टन) वाला कोयला खरीदा गया और उसे उच्च कैलोरी वैल्यू (6,000 किलोकैलोरी/टन) के रूप में भारतीय सरकारी कंपनियों को बेचा गया। उदाहरण के तौर पर, इंडोनेशिया से $28 प्रति टन पर खरीदा गया कोयला भारत पहुंचते-पहुंचते $91-92 प्रति टन का हो गया, जिससे सरकारी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (TANGEDCO) को ऐसे कोयले की आपूर्ति से लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह प्रथा एमसीएल जैसे क्षेत्रीय कोल फिल्ड्स में भी फैल चुकी है, जहां उत्पादित कोयले की ग्रेडिंग में गड़बड़ी से ट्रांसपोर्टरों को प्रभावित किया जाता है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेडर्स लिफ्टरों के द्वारा कम जीसीवी (गुणवत्ता) वाले कोयले की बोली लगाकर डिलीवरी ऑर्डर (डी ओ) प्राप्त करते हैं लेकिन इस डी ओ के आधार पर स्थानीय लिफ्टरों द्वारा हाई जीसीवी कोयला उठाकर चालान किया जाता है 1 जिसमें एमसीएल के अधिकारियों से लेकर फील्ड में काम कर रहे हैं लोडर के ड्राइवर, लिफ्टर, वॉचमैन व कांटा कर्मी तक संलिप्त रहते हैं और महीने के महीने इनको मोटी कमाई इस करस्तानी के बदले में दी जाती है किंतु इसका आकलन किया जाए तो प्रत्येक क्षेत्र/कोलियरी करोड़ों में सीधे तौर पर सरकारी राजस्व की हानी होती है जिस पर ध्यान देकर तुरंत इसे रोकने हेतु जरूरी कार्रवाई की जाए1

2025 में सुंदरगढ़ क्षेत्र में घटनाक्रम के अनुसार अप्रैल 2025 में, सुंदरगढ़ के हेमगिर ब्लॉक में टेलेंडीही राजस्व वन में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का खुलासा हुआ, जहां माफिया द्वारा भारी मशीनरी का उपयोग कर कोयला निकाला जा रहा था16 अप्रैल को, प्रशासन ने 46 टन अवैध कोयला जब्त किया। 18 अप्रैल को, ओडिशा मंत्रियों ने अवैध खनन स्थलों का निरीक्षण किया और 141.76 टन कोयला जब्त किया गया, जो 15-20 वर्षों से चली आ रही समस्या थी। मई 2025 में, ओडिशा सरकार ने ₹39 करोड़ के अवैध खनन की विजिलेंस जांच के आदेश दिए और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की। यह अनियमितताएं निम्न ग्रेड कोयला को उच्च ग्रेड के रूप में उठाने से जुड़ी हैं, जिससे ट्रांसपोर्टरों को अवैध परिवहन में नुकसान हो रहा है।

2025 में झारसुगुड़ा क्षेत्र में घटनाक्रम के तहत अगस्त 2025 में, सीबीआई ने एमसीएल के रामपुर कोल माइंस के सब-एरिया मैनेजर को ₹20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जो कोयला उठाने और ग्रेडिंग में अनियमितताओं से जुड़ा था। मई 2025 में, सुंदरगढ़ घोटाले के बाद झारसुगुड़ा में पावर प्लांट्स और वॉशरीज की जांच शुरू हुई। ये घटनाएं एमसीएल में निम्न ग्रेड कोयला को उच्च ग्रेड के रूप में लोड करने से जुड़ी हैं, जिससे परिवहन में गड़बड़ी बढ़ रही है।

2025 में छेंदीपदा क्षेत्र में घटनाक्रम के अनुसार अगस्त 2025 में, छेंदीपदा ब्लॉक में सुबधरा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट (25 एमटी रिजर्व) के 2025-26 तक चालू होने की योजना से पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ीं, जिसमें हाथियों के विस्थापन का मुद्दा शामिल है। अक्टूबर 2024 में, ग्रामीणों ने ₹8,000 करोड़ के कोयला प्रोजेक्ट के खिलाफ रैली की, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव और भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं की शिकायतें थीं। इसी प्रकार, बैतरनी कोल माइन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जो एमसीएल की परियोजनाओं में स्थानीय विरोध और संभावित अनियमितताओं को दर्शाते हैं। ये मुद्दे कोयला ग्रेडिंग और उठाने में अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, क्योंकि पर्यावरणीय उल्लंघन से अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

2025 में तालचेर क्षेत्र में घटनाक्रम में जनवरी 2025 में, तालचेर के हिंगुला कोल माइन में भूमि धंसाव की घटना हुई, जो सुरक्षा और परिचालन अनियमितताओं को इंगित करती है। जनवरी 2025 में ही, ग्रामीणों ने कनिहा कोल माइन को पंगु बना दिया, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) दावों में देरी की शिकायतें थीं। नवंबर 2024 में, अनुबंधित श्रमिकों की हड़ताल के बाद खनन गतिविधियां फिर शुरू हुईं, लेकिन इससे उत्पादन प्रभावित हुआ। अक्टूबर 2024 में, भूमि अधिग्रहण मामलों के लिए तालचेर में पूर्णकालिक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दी गई, जो पूर्व अनियमितताओं को संबोधित करती है। ये घटनाएं एमसीएल में ग्रेडिंग और परिवहन में गड़बड़ियों से जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हड़तालें और भूमि विवाद अवैध उठाव को बढ़ावा देते हैं।

यह घोटाला न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ट्रक ट्रांसपोर्टरों की आजीविका पर भी असर डाल रहा है। अवैध कोयला परिवहन से ईमानदार सारथियों को काम कम मिल रहा है, जबकि काले बाजार में अनियमित ट्रांसपोर्ट फल-फूल रहा है। इससे बिजली उत्पादन महंगा हो रहा है, जो अंततः आम उपभोक्ताओं पर बोझ डालता है।

हमारी मांगें:

एमसीएल में कोयला ग्रेडिंग एवं उठाने की प्रक्रिया की तत्काल सीबीआई जांच कराई जाए।

ट्रक ट्रांसपोर्टरों को प्रभावित करने वाली अनियमितताओं पर विशेष समिति गठित की जाए।

कोयला मंत्री द्वारा संसद में इस मुद्दे पर बयान दिया जाए एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं, ताकि अवैध परिवहन रोका जा सके।

हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अन्यथा, ₹उफ्तत्सा₹ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा - देशव्यापी आंदोलन शुरू करने को बाध्य होगा।

स्टॉल प्रस्ताव:
सिंगल साइड ओपन स्टोल: 2000
कॉर्नर साइड स्टोल: 3500
तीन साइड ओपन स्टोल: 4500
सिर्फ एक टेबल: 1000
सिर्फ दो टेबल: 1250

कार्यक्रम विवरण:
रक्षा गरबा-डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान: डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें: 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार: 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ:
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें:
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क: इंदु राजपूत
मोबाइल: 9210210071

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण:
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
संपर्क सूत्र: इंदु राजपूत, मोबाइल: 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से

गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर एवं टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) की ओर से रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें:
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है
स्थान: रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली
इंदु राजपूत – 9210210071,
अभिषेक राजपूत 83928 02013,
पिंकी कुंडू 7053533169

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.
MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST
transportvisheshcontent@gmail.com Switch account
The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form
* Indicates required question
How you got aware about TOLWA trust *
- [ ] Social Media
- [ ] News Paper
- [ ] Personal connection
- [ ] Youtube
- [ ] Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

डेंगू व टायफाइड

डेंगू फैला है ! डेंगू प्लेटलेट्स कम होने पर एक चम्मच शहद में गिलोय डंडी रस आधा चम्मच पपीते के पत्ते का रस आधा चम्मच एक बूंद तुलसी रस मिलाकर दिन में तीन बार चटाओ

चार मौसंबी के साथ छह इंच गिलोय सात पत्ते तुलसी का जूस निकाल कर दिन में चार पांच बार दें बहुत शीघ्र रिकवरी होगी

टॉइफाइड फीवर (आंत्रिक ज्वर) या मोतीझरा

इस रोग का गलत प्रबंधन आपको जीवनभर के लिए बीमार और कमजोर बना सकता है

टाइफॉइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन है, जो साल्मोनेला टाइफी (S.typhi) के कारण होता है। टाइफॉइड होने पर तेज बुखार, डायरिया और उल्टी मुख्य रूप से होता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इंफेक्शन के होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। एस. टाइफी मुंह के जरिए आपकी आंतों में प्रवेश करके वहां लगभग एक से तीन सप्ताह तक रहता है। उसके बाद आंतों की दीवार के जरिए आपके रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाता है। खून से ये टाइफॉइड बैक्टीरिया अन्य ऊतकों और अंगों में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं भी नहीं लगा पाती हैं।

टाइफॉइड इलाज ना कराने से आपके लिए घातक हो सकता है। टाइफॉइड की संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर, गंभीर जीआई रक्तस्राव आदि शामिल हैं।

टाइफाइड बुखार छोटी आंत या बड़ी आंत की दीवारों में कोशिकाओं के मरने का कारण बन सकता है जिससे आंतों को स्थाई क्षति पहुंच सकती है

बुखार या ज्वर टाइफाइड का प्रमुख लक्षण है।

जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है वैसे-वैसे ही भूख कम हो जाती है।

टाइफाइड से ग्रसित को सिर दर्द होता है।

शरीर में वेदना होना।

पैरों पिंडलियों जोड़ों में दर्द

ठण्ड की अनुभूति होना।

सुस्ती एवं आलस्य का अनुभव होना सर भारी रहना सिरदर्द।

कमजोरी का अनुभव होना खराब पाचन पेट भरा भरा सूजा हुआ रहना खाने में अरूचि होना

परहेज कोई भी जटिल भोजन न करें मसालेदार तला हुआ मैदा से बनी हुई वस्तुएं ज्यादा मिर्च मसाले वाली वस्तुएं भूलकर भी न खाएं

भूख से थोड़ा कम और खूब चबा-चबाकर खाएं

सफाई और शुद्ध पानी का ध्यान रखें

टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ-कुछ समय बाद तरल पदार्थ जैसे पानी, ताजे फल के रस, हर्बल चाय आदि का सेवन करें।

उबला और उचित तरीके से उबला हुआ पानी पीएं। केवल उबला आहार लें और बाहरी खाने से परहेज करें।

उपचार ये हज़ारों लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर चुका उपाय है जो आंतों को स्वस्थ रखकर उपचार करता है जो सालों साल इस रोग से ग्रस्त थे।

सुबह खाली पेट गिलोय गेहुं ज्वारा और तुलसी का स्वरस 30 मिलीलीटर लें।

खाने के बाद 10/10/10 मिलीलीटर कालमेघासव तथा एक एक आरोग्य वर्धिनी बटी ले तीन समय।

4 अंजीर 8 मुनक्का और चने के दाने बराबर खूबकलां पाउडर कूटकर चटनी बनाकर निराहार चार दिन खिलाएं।

दिन में तीन बार एक चम्मच सौंफ छोटा अदरक सात पत्ते पुदीना एक लौंग एक कप पानी में उबालकर पिलाएं...

ऋषियों की संख्या सात ही क्यों?

हर काल में अलग-अलग सप्तर्षि रहे है। जानिए कौन किस काल के है।

आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तर्षि से उन 7 तारों का बोध होता है, जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है।

ऋषियों की संख्र या सात ही क्यों?...

।।सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय :

कण्डर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च क्रमावश।।

अर्थात:..

1. ब्रह्मर्षि,
२. देवर्षि,
३. महर्षि,
4. परमर्षि,
5. काण्डर्षि,
6. श्रुतर्षि और
7. राजर्षि

ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं इसलिए इन्हें सप्तर्षि कहते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। आओ, संक्षिप्त में जानते हैं कि किस काल में कौन से ऋषि थे।

भारत में ऋषियों और गुरु-शिष्य की लंबी परंपरा रही है। ब्रह्मा के पुत्र भी ऋषि थे तो भगवान शिव के शिष्यगण भी ऋषि ही थे। प्रथम मनु स्वायंभुव मनु से लेकर बौद्धकाल तक ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। हिन्दू पुराणों ने काल को मन्वंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मन्वंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मन्वंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी नामावली इस प्रकार है-

1. प्रथम स्वायंभुव मन्वंतर में- मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ।
२. द्वितीय स्वारोचिष मन्वंतर में- ऊर्ज्ज, स्तम्भ, वात, प्राण, पृषभ, निरय और परीवान।
३. तृतीय उत्तम मन्वंतर में- महर्षि वशिष्ठ के सातों पुत्र।
4. चतुर्थ तामस मन्वंतर में- ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर।
5. पंचम रैवत मन्वंतर में- हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि।
6. षष्ठ चाक्षुष मन्वंतर में– सुमेधा, विरजा, ह्रविष्मान, उतम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु।
7. वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वंतर में- कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज।

भविष्य में –

1. अष्टम सावर्णिक मन्वंतर में- गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यश्रृंग और व्यास।
२. नवम दक्षसावर्णि मन्वंतर में- मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, सबन और भव्य।
३. दशम ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर में- तपोमूर्ति, ह्रविष्मान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु।
4. एकादश धर्मसावर्णि मन्वंतर में- वपुष्मान, घृणि, आरुणि, नि:स्वर, ह्रविष्मान, अनघ और अग्नितेजा।
5. द्वादश रुद्रसावर्णि मन्वंतर में- तपोद्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और तपोधृति।
6. त्रयोदश देवसावर्णि मन्वंतर में- धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकम्प।
7. चतुर्दश इन्द्रसावर्णि मन्वंतर में- अग्नीध्र, अग्नि, बाहु, शुचि, युक्त, मागध, शुक्र और अजित।

इन ऋषियों में से कुछ कल्पान्त-चिरजीवी, मुक्तात्मा और दिव्यदेहधारी है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ....

1. गौतम,
२. भारद्वाज,
३. विश्वामित्र,
4. जमदग्नि,
5. वसिष्ठ,
6. कश्यप और
7. अत्रि।

महाभारत के अनुसार ....

1. मरीचि,
२. अत्रि,
३. अंगिरा,
4. पुलह,
5. क्रतु,
6. पुलस्त्य और
7. वसिष्ठ सप्तर्षि माने गए है।

महाभारत में राजधर्म और धर्म के प्राचीन आचार्यों के नाम इस प्रकार है– बृहस्पति, विशालाक्ष (शिव), शुक्र, सहस्राक्ष, महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज और गौरशिरस मुनि।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी सूची इस प्रकार है- मनु, बृहस्पति, उशनस (शुक्र), भरद्वाज, विशालाक्ष (शिव), पराशर, पिशुन, कौणपदंत, वातव्याधि और बहुदंती पुत्र। वैवस्वत मन्वंतर में वशिष्ठ ऋषि हुए। उस मन्वंतर में उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। वशिष्ठजी ने गृहस्थाश्रम की पालना करते हुए ब्रह्माजी के मार्गदर्शन में उन्होंने सृष्टि वर्धन, रक्षा, यज्ञ आदि से संसार को दिशाबोध दिया ।ऋषियों की संख्र या

सात ही क्यों ?
हर काल में अलग-अलग सप्तर्षि रहे है। जानिए कौन किस काल के है।
आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है। उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सप्तर्षि से उन 7 तारों का बोध होता है, जो ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है।
ऋषियों की संख्र या सात ही क्यों?...
।।सप्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षय :
कण्डर्षिश्च, श्रुतर्षिश्च, राजर्षिश्च क्रमावश।।
अर्थात:..
1. ब्रह्मर्षि,
२. देवर्षि,
३. महर्षि,
4. परमर्षि,
5. काण्डर्षि,
6. श्रुतर्षि और
7. राजर्षि
ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं इसलिए इन्हें सप्तर्षि कहते हैं। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया था। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए। उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। उन्होंने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। आओ, संक्षिप्त में जानते हैं कि किस काल में कौन से ऋषि थे।
भारत में ऋषियों और गुरु-शिष्य की लंबी परंपरा रही है। ब्रह्मा के पुत्र भी ऋषि थे तो भगवान शिव के शिष्यगण भी ऋषि ही थे। प्रथम मनु स्वायंभुव मनु से लेकर बौद्धकाल तक ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी मिलती है। हिन्दू पुराणों ने काल को मन्वंतरों में विभाजित कर प्रत्येक मन्वंतर में हुए ऋषियों के ज्ञान और उनके योगदान को परिभाषित किया है। प्रत्येक मन्वंतर में प्रमुख रूप से 7 प्रमुख ऋषि हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार इनकी नामावली इस प्रकार है-
1. प्रथम स्वायंभुव मन्वंतर में- मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ।
२. द्वितीय स्वारोचिष मन्वंतर में- ऊर्ज्ज, स्तम्भ, वात, प्राण, पृषभ, निरय और परीवान।
३. तृतीय उत्तम मन्वंतर में- महर्षि वशिष्ठ के सातों पुत्र।
4. चतुर्थ तामस मन्वंतर में- ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर।
5. पंचम रैवत मन्वंतर में- हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि।
6. षष्ठ चाक्षुष मन्वंतर में– सुमेधा, विरजा, ह्रविष्मान, उतम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु।
7. वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वंतर में- कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज।
भविष्य में –
1. अष्टम सावर्णिक मन्वंतर में- गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृप, ऋष्यश्रृंग और व्यास।
२. नवम दक्षसावर्णि मन्वंतर में- मेधातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, सबन और भव्य।
३. दशम ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर में- तपोमूर्ति, ह्रविष्मान, सुकृत, सत्य, नाभाग, अप्रतिमौजा और सत्यकेतु।
4. एकादश धर्मसावर्णि मन्वंतर में- वपुष्मान, घृणि, आरुणि, नि:स्वर, ह्रविष्मान, अनघ और अग्नितेजा।
5. द्वादश रुद्रसावर्णि मन्वंतर में- तपोद्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति और तपोधृति।
6. त्रयोदश देवसावर्णि मन्वंतर में- धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकम्प।
7. चतुर्दश इन्द्रसावर्णि मन्वंतर में- अग्नीध्र, अग्नि, बाहु, शुचि, युक्त, मागध, शुक्र और अजित।
इन ऋषियों में से कुछ कल्पान्त-चिरजीवी, मुक्तात्मा और दिव्यदेहधारी है।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ....
1. गौतम,
२. भारद्वाज,
३. विश्वामित्र,
4. जमदग्नि,
5. वसिष्ठ,
6. कश्यप और
7. अत्रि।
महाभारत के अनुसार ....
1. मरीचि,
२. अत्रि,
३. अंगिरा,
4. पुलह,
5. क्रतु,
6. पुलस्त्य और
7. वसिष्ठ सप्तर्षि माने गए है।
महाभारत में राजधर्म और धर्म के प्राचीन आचार्यों के नाम इस प्रकार है– बृहस्पति, विशालाक्ष (शिव), शुक्र, सहस्राक्ष, महेन्द्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज और गौरशिरस मुनि।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी सूची इस प्रकार है- मनु, बृहस्पति, उशनस (शुक्र), भरद्वाज, विशालाक्ष (शिव), पराशर, पिशुन, कौणपदंत, वातव्याधि और बहुदंती पुत्र। वैवस्वत मन्वंतर में वशिष्ठ ऋषि हुए। उस मन्वंतर में उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। वशिष्ठजी ने गृहस्थाश्रम की पालना करते हुए ब्रह्माजी के मार्गदर्शन में उन्होंने सृष्टि वर्धन, रक्षा, यज्ञ आदि से संसार को दिशाबोध दिया।

नारी और वेद

सनातन धर्म की अमर धारा में नारी का स्थान सर्वोच्च और पूजनीय है। वेद नारी को न केवल घर की सम्राज्ञी, बल्कि समाज की आधारशिला, ज्ञान की ज्योति और देवी का स्वरूप मानते हैं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' का यह महान सिद्धांत वेदों से ही निकला है, जहाँ स्त्री को विदुषी, वीरांगना और सुख-समृद्धि की प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि ग्रंथों में नारी के कर्तव्यों, अधिकारों और गरिमा का ऐसा सुंदर चित्रण है, जो अन्य किसी धर्मग्रंथ में दुर्लभ है। यहाँ हम वेदों के आधार पर नारीत्व की पवित्र यात्रा, विवाह के संस्कारों से लेकर पतिव्रत धर्म तक के आदर्शों पर दृष्टि डालेंगे, जो नारी को सशक्त और सम्मानित बनाते हैं।

विवाहकाल में कन्यादान-पाणिग्रहण के बाद लाजाहोम में कन्या अपने लिये अपने मुखसे 'नारी' शब्दका सबसे पहले प्रयोग करती है (पा० गृ० १।६।२, अ० १४।२।६); क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। 'नारीत्व' को प्राप्त करते ही वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने ही वचनमें जीवनके लिये रखती है- १-'आयुष्मानस्तु मे पतिः ।', २-'एधन्तां ज्ञातयो मम ।' मेरा पति पूर्ण आयुसम्पन्न हो और मेरी जाति (समाज) की अभिवृद्धि हो। नारी होनेके बाद ही इसे 'सौभाग्य' की प्राप्ति होती है (अ० १४।१।८, पा० गृ०१।८।९)। सौभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नीरोग स्थिति है ऋ० १०।८६।११)।

पतिमती स्त्रियाँ अविधवा (सधवा) कहलाती हैं। घरमें सधवा स्त्रियोंका प्रथम स्थान है (ऋ० १०।१८।७)। इनको सर्वदा नीरोग, अञ्जन एवं घृतादि स्निग्ध पदार्थोंसे विभूषित, मूल्यवान्धातुओंसे समलंकृत अश्रुविहीन (ऋ० १०।१८।७), सुरूपिणी, हँसमुखी (१।५८।८), शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ, पतिप्रिया (१।७६।), सुवस्त्रा (१०।-७१।४), विचारशीला (१।२८।), पतिपरायणा - (१०।८५।४७) एवं पातिव्रत-धर्मनिष्ठ (पा० गृ० १।-८।८) होना चाहिये। इन्हें अपने सत-कर्तव्योंसे सास, ससुर, देवर तथा ननदके ऊपर साम्राज्य प्राप्त करना चाहिये। नारी होनेके साथ ही इनको 'पत्नी' पद भी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये अपने पतिके लिये कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती हैं (पाणिनि० ४।१।)। शास्त्रीय विधानसे पुरुष-सम्बन्ध होनेपर ही स्त्री व्यक्ति-पत्नी कहलाती है।

पत्नी पुरुषका आधा स्वरूप है (तै० ब्रा० ।५)। इस पत्नीके बिना पुरुष अधूरा रहने (श० ५।२।१।१०) के कारण सब यज्ञोंका अधिकारी नहीं बनता (तै० २।२।२।६)। पत्नी लक्ष्मीका स्वरूप है (श० १२।६।७)। इसका पूजन (सत्कार) करना चाहिये (मनु० ५६)। पुरुषोंद्वारा स्त्रियोंकी पूजा उनके कर्तव्योंसे की जाती है। पुरुषको संसारमें फँसा देनेमात्रसे पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती (१।९२।)।

पुरुषोंद्वारा सम्मानित होनेके कारण स्त्रियोंका वैदिक नाम 'मेना' (निरु० ।४।२१) है। पति इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता है, इसलिये इसे 'जाया' कहते हैं (ऐ० ब्रा० ७।१)। पुत्र-संततिसे स्त्रीकी प्रशंसा है (ऋ० १०।८६।९)। बीस संतति होनेपर भी जिसके शरीरमें विकृति न आये, वह स्त्री महत्त्वशालिनी है (ऋ० १०।८६।२), साधारण स्त्रीमें दस संततिका आधान होना चाहिये (१०।८५।४५)। अधिक संतति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता है (२।२०)। स्त्रीके अङ्गोंमें बाहु, अँगुली (२।२।७), भग (१०।८६।६)-की शोभनता, केशकी पृथुता (१०।८६।८), कटिभाग (श० ।५।१।११), जघनकी विशालता (१०।८६।८), मध्यभागकी कृशता (श० १।२।५।१६)-की प्रशंसा वेदोंमें मिलती है।

स्त्रीको इस तरह (लज्जापूर्ण) रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप देखता हुआ भी न देख सके, वाणी सुनता हुआ भी पूरी न सुन सके (अर्थात मन्दवाणी बोलनी चाहिये) (१०।७१।४)।

वेदों के इन अमूल्य मंत्रों से स्पष्ट है कि नारी वास्तव में शक्ति का प्रतीक है—जो न केवल परिवार की धुरी है, बल्कि समाज और संस्कृति की रक्षक भी। आज के युग में, जब नारी सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, वेद हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति कर्तव्यनिष्ठा, गरिमा और पूजनीयता में निहित है।

सत्य सनातन धर्म की जय

गुड़ एक आयुर्वेद औषधि

गुड़ जिसका सेवन सबसे ज्यादा ठंड में किया जाता है ? पर कुछ लोग बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन करते है इस सोच के साथ की ज्यादा गुड़ खाने से नुकसान होता है। इसकी प्रवृति गर्म होती है, लेकिन ये एक गलतफहमी है गुड़ हर मौसम में खाया जा सकता है और पुराना गुड़ हमेशा औषधि के रूप में काम करता है। आयुर्वेद संहिता के अनुसार यह शीघ्र पचने वाला, खून बढ़ाने वाला व भूख बढ़ाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त गुड़ से बनी चीजों के खाने से बीमारियों में राहत मिलती है। गुड़ में सुक्रोज 59.7 प्रतिशत, ग्लूकोज 21.8 प्रतिशत, खनिज तरल 26प्रतिशत तथा जल अंश 8.86 प्रतिशत मौजूद होते हैं।इसके अलावा गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और ताम्र तत्व भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसलिए चाहे हर मौसम में आप गुड़ खाना न पसन्द करें लेकिन ठंड में गुड़ जरूर खाएं।

यह सेलेनियम के साथ एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। गुड़ में मध्यम मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस व जस्ता पाया जाता है यही कारण है कि इसका रोजाना सेवन करने वालों का इम्युनिटी पॉवर बढ़ता है। गुड़ में मैग्नेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है इसलिए ये बॉडी को रिचार्ज करता है साथ ही इसे खाने से थकान भी दूर होती है।

गुड़ और काले तिल के लड्डू खाने से सर्दी में अस्थमा परेशान नहीं करता है। रोजाना गुड़ का सेवन हाइब्लडप्रेशर को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें रोज थोड़ी मात्रा में गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे शरीर में हिमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है।

गुड़ का हलवा या लड्डू खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है व सर्दियों में, यह शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है।

अगर आप गैस या एसिडिटी से परेशान हैं तो खाने के बाद थोड़ा गुड़ जरूर खाएं ऐसा करने से ये दोनों ही समस्याएं नहीं होती हैं। गुड़, सेंधा नमक, काला नमक मिलाकर चाटने से खट्टी डकारें आना बंद हो जाती हैं।

श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन क्यों अनिवार्य है

(अध्यात्म एवं सनातन संस्कृति)

धर्मशास्त्र के अनुसार श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से मिलता है पितरों का आशिर्वाद एवं अपने घर परिवार में मिलती है यश एवं शांति। साथ ही अनिष्टकारी ग्रहों से मिलता है छुटकारा।

(१) धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने का मध्याह्न का समय दोपहर 11:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक का समय अति उत्तम माना गया है।

(२) धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह 11:30 बजे से पहले किया गया तर्पण,पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मणों को कराया गया भोजन पितरों तक कतई नहीं पहुंचता है यह सिर्फ रस्म अदायगी मात्र ही है और वहा से पितर रूष्ट होकर श्राप देकर लौट जाते हैं।

( ) धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिन श्राद्ध के समय श्राद्ध की तिथि का होना अति आवश्यक है।

(४) जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध करने के लिए कुछ भी ना हो तो सूर्य भगवान के आगे दोनों हाथों उठाकर (आकाश की तरफ) कहें - हे मेरे पितृगण मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त न तो धन है न धान्यादि हां मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है मैं इन्हीं के द्वारा आप को तृप्त करना चाहता

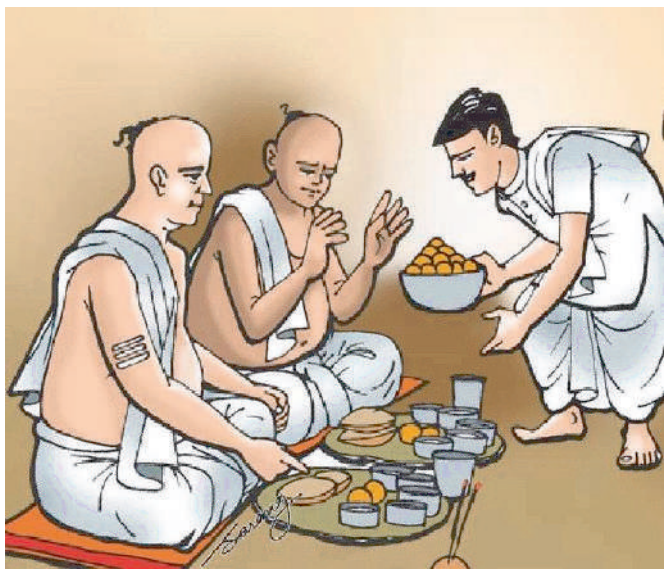

हूं। आप तृप्त हो जाए उसके पितर कहीं भी किसी भी योनि में हो उनको उसी रूप में अमृत रूपी अन्न प्राप्त होगा।

(५) धर्मशास्त्र के अनुसार जो लोग श्राद्ध के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन न करा कर टिफिन पैक करके ब्राह्मण के घर पर पहुंचा देते हैं या अन्य स्थान पर भोजन का टिफिन पैक करके पहुंचा देते हैं।

*यह शास्त्र सम्मत सही नहीं है इससे श्राद्ध का फल नहीं मिलता है और वहां से पितर रुष्ठ होकर श्राप देकर लौट जाते हैं।

(६) जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते है कई कल्पों तक उनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है और मृत आत्मा के पुत्र पौत्रादी सगे संबंधी पग पग पर कष्टो का सामना करते हैं।

झारखंड में तेईस लाख दाखिल-खारिज मामले मेसे दस लाख डिस्पोज, ग्यारह लाख रिजेक्ट

सरायकेला। खरसावां माफियाओं का भूस्वर्ग पर सरकार के लिये गले का फांस, अगर केंद्र, ओडिशा या कोर्ट करवा दे वाह्य एजेन्सी से जांच !

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

राची। राज्यभर में म्यूटेशन(दाखिल-खारिज) के कुल 23 लाख 19 हजार 243 केस आए. इसमें से 10 लाख 76 हजार 928 केस को डिस्पोज किया गया. 11 लाख 71 हजार 696 केस रिजेक्ट कर दिए गए. 70,622 केस पेंडिंग हैं.

धनबाद, रांची और हजारीबाग में सबसे अधिक केस रिजेक्ट किए गए. रांची में सबसे अधिक तीन लाख चार हजार 476 केस खारिज किए गए. धनबाद में 1,50,237 और हजारीबाग में 1,27,257 केस रिजेक्ट किए गए. वहीं बोकारो में 71,074 और पलामू में 70,011 केस खारिज किए गए.

बात सरायकेला खरसावां जिले से की जाय तो दोनों ओड़िया देशी रियासत रहा है । बाद में ओडिशा का राजस्व जिला भी । जहां के जिला धिकारी ओडिशा कैडर के दुर्गा दास रहे ।

आजादी समय के ठीक बाद राजनीति में यहां जमीन की लूट बिहार झारखंड की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार हो सकती है , बशर्ते स्वतंत्र एजेंसी से सही जांच हो । दोनों ही जिला में पूर्व मे जमीन दस्तावेज ओड़िया भाषा में रहा है । जिसे वहां आज भी का ओड़िया भाषा पार्चा कहा जाता। आजादी के बाद जहां स्वतंत्र भारत का प्रथम गोलीकांड नियोजित तरीके से खरसावां गोलीकांड कराया जाता है । फिर एक साल के लिये इसे बिहार में महज किस लिए भेजा जाता कि मयूरभंज का विलय स्वतंत्र भारत वर्ष मे यथा समय नहीं हो पाया था । इसी बीच बिहार ने सरायकेला खरसावां को उड़ीसा को आज तक नहींलट आया है । जो जमीन लोगों की थी उसे एन केन प्रकारण 1964 सेटलमेंट में लूट की गयी । कारण बिहार सरकार के अधिकारियों ने जिस प्रकार कार्य किया वह स्वतंत्र भारत वर्ष में कहीं और हुआ ही नहीं है । फिर बिहार अब झारखंड में आज भी दाखिल खरिज के अनेकों अवैध मामले किस राजस्व अधिकारी को निगल कहां जाय कहा नहीं जा सकता । कारण हर सीओ का कार्यालय में जमीन चरों का जमाबड़ा है । सरकारी स्कूलों के मास्टर, सरकारी सेवक, व्यापारी, अधिकारी सभी यहां बडे जमीन खरीदार बने हुए हैं । जिनको सफेदपोश फंडिग करते हैं ।यह इतना बड़ा संगीन अपराध का मामला है कि इसकी निष्पक्ष जांच कभी भी न्यायपालिका या गृहमंत्रालय करा सकता है ।

तीनों सिंहभूम जले में खाता-2 फटे होने की बात कही जाती पर अनेकों जमीन निबंधित फिर ओन लाइन अपलोड कैसे हुआ है यह गुड रहस्य भ्रष्टाचार के मकड़े जाल में फंसा हुआ है । एक बड़ा पीड़ित जन समुह सरकार के इस बृहत भ्रष्टाचार पर आज खपा है ।जिसका मुख्य कारण निकाली दलालों के कहने पर पुलिस के जरिये धमका रहे हैं तो कही निरीह लोगों पर फर्जी मामले दायर करवा चुके हैं ।

जिला वार कितने म्यूटेशन रिजेक्ट हुए उसकी जानकारी निम्नानुसार है।

कोडरमा 45,656,खूंटी 15,873,गढ़वा 34,349, गुमला 77,832,गोड्डा 1155,चतरा 32,302,जामताड़ा 1170,दुमका 6127,देवघर 15979,धनबाद 1,50,237,पूर्वी सिंहभूम 35,349,पलामू 70,011,

पश्चिमी सिंहभूम 10,937,पाकुड़ 47,083,बोकारो 71,074,रांची 3,04,476,रामगढ़24,037,लातेहार 14,501,लोहरदगा 12,148,सरायकेला खरसावां 31,663,साहेबगंज21,709,सिमडेगा 5174,हजारीबाग1,27,257 है ।।

झारखंड में एक करोड़ रू की हाथी की चोरी, पलामू थाने में दर्ज हुआ

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

मेदिनीनगर। आपने अबतक कार, बाइक, धनराशि, गहने, ज़ेवरात यहां तक की हवाई जहाज आदि चोरी की घटना सूनी होगी पर इक्कीसवीं सदी में झारखंड में अब एक अनोखी घटना सामने आई है । जहां एक हाथी चोरी हुई है ,हाथी मालिक ने पुलिस से हाथी बरामद कराने की फरियाद करते हुए महावत पर चोरी का आरोप दर्ज कर दी है ।

घटना पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट गांव से एक हथिनी चोरी हो गई ।जिसका नाम जयमनी है । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहनेवाले नरेंद्र कुमार शुक्ला ने शनिवार को सदर थाने में संबंधित महावत के खिलाफ हाथी के साथ लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई है। पलामू की एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, नरेंद्र कुमार शुक्ला के पास हाथी रखने का लाइसेंस है ।उन्होंने 11 अगस्त को हथिनी को रांची भेजा था। लौटने के क्रम में पलामू के जोरकट के पास नरेंद्र ने उस हथिनी को दो महावत के हवाले कर यह कहते हुए मिर्जापुर लौट गए थे कि आपलोग हथिनी के साथ मिर्जापुर पहुंचें। जब महावत हथिनी को लेकर मिर्जापुर नहीं पहुंचा, तब उन्होंने खोजबीन शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर नरेंद्र ने शनिवार को मेदिनीनगर सदर थाने में प्राथमिकी कराई। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर हथिनी और उसके महावत की खोजबीन शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के एसडीपीओ मणि भूषण प्रसाद ने बताया कि हाथिनी के पालक नरेंद्र कुमार शुक्ला ने प्रारंभिक पूछताछ के बताया है कि चारे की कमी के कारण हाथी को लेकर झारखंड के गांव में महावत के साथ आए थे। मेदिनीनगर सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आवेदन के अनुसार, नरेंद्र को अपने क्षेत्र के एक महावत से हथिनी जिम्मेनामा पर मिली थी। मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी गई है।यूपी के मिर्जापुर निवासी हाथी पालक नरेंद्र शुक्ला ने बातचीत में कहा कि मेरे परिवार में हाथी पालने की परंपरा रही है। यह पूजा-पाठ में काम आता है। उनके रिश्तेदार ने इस हाथी को असम से प्राप्त किया था। उस रिश्तेदार से नरेंद्र ने करीब एक साल पहले हाथी को प्राप्त किया था। उनके महावत और एक अन्य व्यक्ति ने हाथी को गायब कर दिया है। इधर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के पूर्व सदस्य डॉ डीएस श्रीवास्तव ने बताया कि हाथी की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। जिन्हें पूर्व में हाथी पालने का लाइसेंस प्राप्त है, उसमें भी प्रावधान को कड़ा किया गया है। हाथी की बिक्री भारतीय बाजार में 50 लाख

रुपये तक में होती थी। वर्तमान में इसकी बिक्री प्रतिबंधित हो जाने और पालने में परेशानी के कारण महावत के जिम्मे उसके मालिक हाथियों को छोड़ देते हैं। महावत हाथी को छोड़कर भाग भी जाते हैं। इस कारण ऐसे हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाया गया है।

पत्रकारिता की नैतिकता: चाटुकारिता से परे, सत्य की रक्षा में घटनाओं का साक्ष्य

पत्रकारिता समाज का आईना है, जो सत्ता, शक्ति और सत्य के बीच संतुलन बनाए रखने का दायित्व निभाती है। कथन—"पत्रकार चाटुकारिता नहीं करते व जो चाटुकारिता करते हैं वे पत्रकार नहीं होते"—इस पेशे की मूल भावना को स्पष्ट करता है। चाटुकारिता, अर्थात सत्ता की अंधी प्रशंसा या हितों की रक्षा, पत्रकारिता की आत्मा को खोखला कर देती है। इस लेख में हम इस कथन की विस्तृत तथ्यात्मक व्याख्या करेंगे, साथ ही ऐतिहासिक और वर्तमान घटनाओं को दर्शाते हुए समझेंगे कि कैसे सच्चे पत्रकार चाटुकारिता से दूर रहकर समाज को मजबूत बनाते हैं, जबकि चाटुकारिता करने वाले मात्र प्रचारक बनकर रह जाते हैं। यह विश्लेषण न केवल पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि वास्तविक घटनाओं से समृद्ध है, जो दर्शाती हैं कि चाटुकारिता लोकतंत्र के लिए कितनी हानिकारक है।

चाटुकारिता का अर्थ और पत्रकारिता में उसकी भूमिका

चाटुकारिता वह व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति सत्ता या प्रभावशाली व्यक्तियों की प्रशंसा करता है, सत्य को नजरअंदाज करके या विकृत करके। पत्रकारिता के संदर्भ में, यह समाचारों को सरकार या कॉर्पोरेट हितों के अनुरूप ढालना है। उदाहरणस्वरूप, यदि कोई मीडिया हाउस सरकार की नीतियों की आलोचना करने के बजाय उनकी अंधी तारीफ करता हैअंधभक्त बनता है, तो यह चाटुकारिता है। तथ्यात्मक रूप से, पत्रकारिता सत्य की खोज है, न कि सत्ता की सेवा। दार्शनिक - इमैनुएल कांट के अनुसार, ₹सत्य एक नैतिक कर्तव्य है, जो किसी भी व्यक्तिगत लाभ से ऊपर है। चाटुकारिता इस कर्तव्य को भंग करती है, और जो ऐसा करता है, वह पत्रकारिता के पेशे से बाहर हो जाता है।"

विश्व स्तर पर, चाटुकारिता मीडिया की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। एक अध्ययन के अनुसार, मीडिया का कॉर्पोरेट नियंत्रण और राजनीतिक दबाव चाटुकारिता को बढ़ावा देता है, जिससे जनता का विश्वास घटता है। भारत में, मुख्यधारा मीडिया का सरकार की ओर झुकाव एक प्रमुख समस्या है, जहां विज्ञापन और टीआरपी सत्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांत: तथ्यात्मक आधार

पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांत चाटुकारिता से पूरी तरह असंगत हैं। मुख्य सिद्धांत हैं:

सत्य की खोज: पत्रकार को तथ्यों की जांच करनी चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों से प्रभावित होना।

निष्पक्षता: सभी पक्षों को समान अवसर देना, जैसा कि अमेरिकी सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स के कोड में उल्लिखित है।

जनहित: जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावाद के अनुसार, पत्रकारिता अधिकतम लोगों के हित में होनी चाहिए, न कि सत्ता के।

स्वतंत्रता: भारतीय संविधान का अनुच्छेद १९(१)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह चाटुकारिता की नहीं, सत्य की स्वतंत्रता है।

ये सिद्धांत दर्शाते हैं कि चाटुकारिता पत्रकारिता को एक प्रचार तंत्र में बदल देती है। नाइजीरिया जैसे देशों में चाटुकारिता सनसनीखेज खबरों को जन्म देती है, जो मीडिया की जिम्मेदारी से विचलन है।

ऐतिहासिक घटनाएं: चाटुकारिता के विरुद्ध पत्रकारिता का संघर्ष

इतिहास में कई घटनाएं हैं जहां पत्रकारों ने चाटुकारिता से इंकार कर सत्य उजागर किया:

वाटरगेट स्कैंडल (१९७२, अमेरिका): वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के मुख्यालय में सेंधमारी की जांच की। उन्होंने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रशासन की संलिप्तता उजागर की, जिससे निक्सन को १९७४ में इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना ने पत्रकारिता को बदल दिया, जांच पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया और दुनिया भर में लाखों पत्रकारों को प्रेरित किया। यदि वे चाटुकारिता करते, तो अमेरिकी लोकतंत्र पर गहरा आघात लगता।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम: बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' अखबार में ब्रिटिश सत्ता की चाटुकारिता नहीं की। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण पर लिखा, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसी तरह, गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' में सत्य लिखा, भले ही इसका मतलब खतरा हो। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सच्चे पत्रकार चाटुकारिता से दूर रहते हैं।

इन घटनाओं से स्पष्ट है कि चाटुकारिता इतिहास में भुला दी जाती है, जबकि सत्य की रक्षा करने वाले अमर हो जाते हैं।

वर्तमान घटनाएं: भारत और विश्व में चाटुकारिता vs. सत्यनिष्ठा

वर्तमान में, चाटुकारिता एक वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत में यह अधिक स्पष्ट है:

चाटुकारिता के उदाहरण: मोदी सरकार के दशक में, मीडिया की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। कई मीडिया हाउस सरकार की नीतियों की अंधी प्रशंसा करते हैं, जबकि आलोचना को दबाते हैं। सरकार के विज्ञापनों पर निर्भरता चाटुकारिता को बढ़ावा देती है। उदाहरणस्वरूप, २०२० में किसान आंदोलन के दौरान, कुछ मीडिया ने प्रदर्शनकारियों को 'खालिस्तानी' बताकर सरकार का पक्ष लिया, जबकि तथ्य विपरीत थे। हाल ही में, भारत की डिसइनफॉर्मेशन कैंपेन में मीडिया ने कनाडा के खिलाफ झूठी खबरें फैलाईं, जैसे निज्जर मामले में आरोप हटने की अफवाह।

प्रतिरोध के उदाहरण: इसके विपरीत, कई पत्रकार चाटुकारिता से इंकार कर रहे हैं। राना अय्यूब, जो सरकार की आलोचना करती हैं, को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर जन मुद्दों पर फोकस किया, भले ही ट्रोलिंग और धमकियां मिलीं। मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक, को २०२२ में एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने फेक न्यूज का खंडन जारी रखा। उत्तर प्रदेश में, ६६ पत्रकारों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन वे लगातार सत्य लिखते रहे।

विश्व स्तर पर, प्रोपब्लिका के जेसी ईसिंगर जैसे पत्रकार कॉर्पोरेट और राजनीतिक दबाव के बावजूद जांच जारी रखते हैं। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि सच्चे पत्रकार चाटुकारिता नहीं करते, जबकि करने वाले मात्र सरकारी मुखपत्र बन जाते हैं।

चुनौतियां और समाधान -

वर्तमान चुनौतियां व्यावसायीकरण, राजनीतिक दबाव और डिजिटल फेक न्यूज। भारत में, २०२० में ६७ पत्रकार गिरफ्तार हुए और २०० पर हमले। समाधान हैं: नैतिक शिक्षा, संपादकीय स्वतंत्रता, जन जागरूकता और कानूनी सुरक्षा। एआई जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए, पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखनी होगी।

निष्कर्ष-

यह कथन एक तथ्यात्मक सत्य है: पत्रकार चाटुकारिता नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना उन्हें पत्रकारिता से बाहर कर देता है। वाटरगेट से लेकर राना अय्यूब तक की घटनाएं दर्शाती हैं कि सत्य की रक्षा लोकतंत्र को मजबूत करती है, जबकि चाटुकारिता उसे कमजोर। आइए, हम सच्ची पत्रकारिता का समर्थन करें, जो घटनाओं से सीखते हुए आगे बढ़े।

-डॉ राजकुमार यादव
(सदस्य प्रेस क्लब ऑफ़ इण्डिया)

एमएसएमई और एनएसआईसी का महत्व: व्यवसाय की मजबूत नींव के लिए आवश्यक शिक्षा

डॉ. अंकुर शरण

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में छोटे और मध्यम उद्यम (MSME – Micro, Small and Medium Enterprises) अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। वहीं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC – National Small Industries Corporation) ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो युवाओं, नवोदित उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को व्यवसाय शुरू करने, बढ़ाने और टिकाऊ बनाने में मदद करता है।

व्यवसाय की शुरुआत में MSME और NSIC क्यों जरूरी हैं?

कई बार युवा या नवोदित उद्यमी उत्साह में व्यवसाय शुरू कर तो देते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन, वित्तीय योजना, बाज़ार की समझ और तकनीकी जानकारी न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। MSME और NSIC जैसे संस्थान उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण, सरकारी योजनाओं की जानकारी, वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ने के अवसर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराते हैं।

व्यवसाय की योजना बनाना – बाजार की मांग, उत्पाद की गुणवत्ता, लागत और लाभ का विश्लेषण करना सिखाया जाता है।

वित्तीय प्रबंधन – बैंक लोन, सब्सिडी, सरकारी योजनाओं के तहत ऋण लेने के तरीके समझाए जाते हैं।

नेटवर्किंग और मार्केटिंग – छोटे उद्योगों को बड़े बाजार से जोड़ने, सरकारी खरीद में भागीदारी का अवसर और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जाती है।

तकनीकी प्रशिक्षण – उत्पादन की दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण, उपकरणों का सही उपयोग और ऊर्जा की बचत जैसे विषयों पर मार्गदर्शन।

सरकारी योजनाओं का लाभ – एनएसआईसी कई योजनाओं के तहत टेंडर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तकनीकी सहायता और निर्यात सहायता प्रदान करता है।

व्यवसाय में मूल्य जोड़ने के अवसर

MSME और NSIC केवल मदद करने वाले प्लेटफ़ॉर्म नहीं हैं, बल्कि व्यवसाय में मूल्य जोड़ने का आधार भी हैं। सही मार्गदर्शन से आप: https://www.msmemart.com/

नवाचार ला सकते हैं – नए उत्पाद विकसित कर सकते हैं या पुरानी प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं।

ग्राहकों की ज़रूरत समझ सकते हैं – बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार सेवा और उत्पाद में बदलाव कर सकते हैं।

सही लागत पर उत्पादन कर सकते हैं – संसाधनों का बेहतर उपयोग कर खर्च कम और लाभ बढ़ा सकते हैं।

संपर्क नेटवर्क बढ़ा सकते हैं – बड़े ग्राहकों, सरकारी संस्थाओं और निर्यातकों तक पहुंच सकते हैं।

विश्वसनीयता हासिल कर सकते हैं – प्रमाणपत्र, गुणवत्ता मानक और तकनीकी समर्थन से अपने व्यवसाय की ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं।

युवाओं के लिए सीख

व्यवसाय केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि समाज में योगदान देने का एक अवसर है। MSME और NSIC के माध्यम से आप:

✓ अपने विचार को व्यवसाय में बदल सकते हैं।
✓ रोजगार सृजन कर सकते हैं।
✓ स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर क्षेत्रीय विकास में योगदान कर सकते हैं।
✓ सतत और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय मॉडल विकसित कर सकते हैं।

यदि आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को नए स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो MSME और NSIC जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल आपको व्यावहारिक ज्ञान देंगे, बल्कि आपकी सोच को व्यापक बनाकर आपके व्यवसाय को स्थायी सफलता की ओर ले जाएंगे।

मेरी आप सभी युवाओं से यही अपील है कि व्यवसाय की शुरुआत में धैर्य रखें, सीखने की प्रवृत्ति अपनाएं और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं।

— डॉ. अंकुर शरण
(लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ और सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता)

ब्रिटेन नस्लीय भेदभाव को लेकर नेशनल अकाली दल ब्रिटेन सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन

मुख्य संवाददाता

दिल्ली :ब्रिटेन के ओल्डबरी इलाके में एक सिख महिला के साथ दिनदहाड़े पार्क में गैंगरेप करके आरोपियों ने पीड़िता को ₹अपने देश वापस जाओ₹ कहकर नस्लीय भेदभाव भी जताया। नेशनल अकाली दल (एनएडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा कि सिख समुदाय में इसको लेकर काफी रोष है। जल्द ही इसको लेकर नेशनल अकाली दल ब्रिटेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा।

पम्मा ने कहा ब्रिटेन में हाल के महीनों में नस्लीय उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं सिख समुदाय में इसको लेकर बड़ा डर का माहौल है।

पम्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि ब्रिटेन में सिख समुदाय के

लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं सिख समुदाय के लोगों को डराने और परेशान करने के लिए काफी हैं।

पम्मा ने ब्रिटेन सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और सिख समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे ब्रिटेन में नस्लीय हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो चिंता का विषय है। सिख समुदाय के लोगों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिसमें पगड़ी का अपमान और नस्लीय टिप्पणियां शामिल हैं।

पम्मा ने ब्रिटेन सरकार से मांग की जा रही है कि वह नस्लीय हमलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और सिख समुदाय के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे साथी उन्होंने भारत सरकार से भी हस्तक्षेप करके ब्रिटेन सरकार पर दबाव बनाए। वहां पर जो नक्सलवादी घटनाएं हो रही है उसे पर रोक लगा सके।

पम्मा ने कहा इस प्रकार की घटनाओं को लेकर नेशनल अकाली दल जल्द ही ब्रिटेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा।

एक्टर, सिंगर, सांसद श्री मनोज तिवारी निभायेंगे भगवान परशुराम का किरदार

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। लालकिला मैदान में आयोजित विश्व विख्यात लव कुश रामलीला कमेटी की एक प्रेस वार्ता में कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने मीडिया को बताया इस वर्ष लीला कमेटी ने जेन एक्स को प्रभु श्रीराम की लीला के प्रति और अधिक आकर्षित करने, देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने की भावना को उजागर करने के मकसद से इस बार निमंत्रण पत्रों पर जल, थल एवं वायु सेना के शौर्य, पराक्रम को दिखाते चित्र प्रकाशित किए गये है।

अर्जुन कुमार ने कहा मशहूर एक्टर सिंगर और सांसद मनोज तिवारी इस वर्ष रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे हैं, इससे पूर्व भी केवट और अंगद आदि का किरदार भी निभा चुके है। ए आई तकनीक से बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म रामायण रामलीला मंचन से पूर्व प्रतिदिन रामभक्तों को दिखाई जायेगी ।

देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप, विशाल भंडारा, स्पेशल स्कूली बच्चों को बैग वितरण, स्टेशनरी, महिलाओं को साड़ी वितरण किया जायेगा। इस अवसर पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से दिव्यांगों को मोटराइज्ड, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर वितरित की जायेगी। तारा नेत्रालय के सहयोग निशुल्क आंखों की जांच, मोतियाबिंद आपरेशन और नजर के चश्मों का वितरण होगा। एल्पस के सहयोग से कानों की मशीन निशुल्क वितरण की जाएगी। रक्तदान शिविर ओर पूरे दिन भंडारे का आयोजन होगा।

सांसद, अभिनेता, सिंगर मनोज तिवारी ने कहा कि लालकिला के ऐतिहासिक ग्राउण्ड में हजारों राम भक्तों के सामने परशुराम जी का किरदार निभाना मेरे लिए गौरव की बात है, मैं बचपन से ही रामलीला से जुडा हूँ जब मुझे अर्जुन कुमार और सुभाष गोयल ने लीला में कोई किरदार निभाने का आमंत्रण दिया जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । सांसद मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि हमें रामकाज के लिए रामलीलाओं से हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए इससे भारतीय संस्कृति और प्रभु श्री राम की शिक्षा, युवा पीढ़ी जान सके और उसका अनुसरण कर सके।

कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल के अनुसार लीला के प्रथम दिन गणेश पूजन से लीला प्रारंभहोगी और इसके बाद मंचन पर महर्षि वाल्मिकी द्वारा लव कुश को रामकथा और प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन प्रस्तुत करने का दृश्य और तुलीदास जी जीवनी के दृश्य भी प्रस्तुत किए जायेंगे। इस वर्ष भी लीला के प्रमुख पात्रों को बालीबुड और टीवी फील्ड के अनेक जाने माने कलाकार निभाएंगे । इनमें प्रमुख है किनसुक बैध (राम), डा. राजन शर्मा (लक्ष्मण), रिनी आर्या (सीता), मल्हार पांडया (हनुमान), आर्य बब्बर (रावण), राजेश पुरी (राजा जनक के मंत्री), शंकर साहनी (केवट), डा. अशोक शर्मा (सुसेन वैध) आदि ।

लव कुश रामलीला कमेटी के चैयरमेन पवन गुप्ता और सीनियर वाईस प्रसिडेंट सत्यभूषण जैन ने लीला मंचन 22 सितम्बर से प्रारंभ होगा 3 अक्तूबर 2025 को भरत मिलाप के साथ लीला सम्पन्न होगी, दशहरा पर्व 02 अक्तूबर को बड़ी धूम धाम से सम्पूर्ण विश्व में सम्पन्न होगा ।

कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल सिंहल के अनुसार बाबा खाटू श्याम के मधुर भजनों का एक विशेष कार्यक्रम विख्यात भजन गायक और खाटू श्याम के परम भक्त कन्हैया मित्तल और उनकी पार्टी द्वारा किया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा था, "ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऑपरेशन क्रिकेट कैसे जारी है?- संजय सिंह

मुख्य संवाददाता

नईदिल्ली, आम आदमी पार्टी ने रविवार को होने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध करते हुए देशवासियों से इसका वहिष्कार करने की अपील की है। ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को देश के शहीदों का अपमान बताया है। वहीं, ''आप'' के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में लोकसभा के सभी पदाधिकारियों को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का वहिष्कार करने की कसम दिलाई है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ ग़द्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद ग़ुस्से में है।

''आप'' के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बड़े गर्व से कहा था कि बात और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। लगता है कि देशभक्ति केवल प्रधानमंत्री के भाषणों तक ही सीमित है। अब तो पूरा देश पूछ रहा है क्या ऑपरेशन सिंदूर की चिताएं इतनी जल्दी ठंडी पड़ गईं कि आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, जवाब दीजिए।

सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यह घटना अंजाम दी। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, आम नागरिक मारे गए और एक एडीसी भी शहीद हुए। जिस पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही है, उसके साथ कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं? भारत सरकार ने खुद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। यह भी प्रधानमंत्री का बयान है। तो फिर खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? चूंकि क्रिकेट में इन लोगों के बेटों का धंधा जुड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए की कमाई जुड़ी हुई है। देश, उसका स्वाभिमान और सम्मान भाड़ में जाए, लेकिन इनके बेटों की कमाई नहीं रुकनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश के लोगों को समझना होगा कि ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, जो बार-बार देशभक्ति की बात करते हैं, इनके लिए धंधा पहले है, इनके लिए देश बहुत पीछे है। इन्हें क्रिकेट के धंधे में करोड़ों की कमाई और सट्टेबाजी करनी है। इनके लिए इस धंधे में देश कहीं नहीं ठहरता। जो नौजवान इनके पीछे पागल होते हैं, मोदी-मोदी के नारे लगाते हैं, उन्हें इनका दोहरा चरित्र समझना होगा। जब इनका धंधा चल रहा है, तब इनको पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। दुबई, कतर या कोई भी जगह हो, इनका धंधा चलता रहे, तब इनको कोई समस्या नहीं है।

संजय सिंह ने कहा कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। फिर भी क्रिकेट खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शनिवार को एक बेतुका बयान दिया कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलना मजबूरी है। अनुराग ठाकुर बताएं कि अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन हैं। उन्हें यह फैसला लेना चाहिए था। इसलिए साफ है कि भाजपा के लिए देश नहीं, धंधा पहले है।

उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में सभी लोकसभा के सभी पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का वहिष्कार करने की कसम दिलाई। उन्होंने एक्स पर कहा कि एक-एक लोकसभा के पदाधिकारी क़सम खा रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सिपाही देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए एक्स पर कहा कि आतंकियों को पनाह देने वाले देश के साथ क्रिकेट खेलना हमारे शहीदों का अपमान है।

हालात से हाथ मिलाती दुनिया....

आज का दौर इंसानी रिश्तों और संवेदनाओं की बजाय हालात से हाथ मिलाने वाला दौर बन चुका है। लोग सीधे इंसान से नहीं, बल्कि उसके हालात से, उसकी मजबूरी और उसकी स्थिति से जुड़ते हैं। किसी की असल शख्सियत, उसका चरित्र या उसका दिल देखने की फुर्सत अब बहुत कम लोगों के पास बची है। लोग यह सोचते हैं कि सामने वाले की हालत कैसी है, वह ताक़तवर है या कमज़ोर, अमीर है या ग़रीब, सफल है या असफल। अगर हालात मज़बूत हैं, तो दुनिया साथ होती है, और अगर हालात डगमगा जाएँ तो वही लोग दूर हो जाते हैं। यही इस दौर की कड़वी सचाई है। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान केवल अपने सपनों के भरोसे न रहे, बल्कि अपने हालातों को मज़बूत बनाए। दुनियावालों की नीयत को समझो, ताकि किसी भ्रम में न जीना पड़े। हर रिश्ता और हर जुड़ाव हमेशा आत्मीय नहीं होता, कभी-कभी उसके पीछे स्वार्थ और लाभ की परछाई छिपी होती है। अगर हालात मज़बूत होंगे तो दुनिया इज़्ज़त भी देगी, कंधा भी थामेगी और मुस्कुराकर स्वागत भी करेगी। मगर जब हालात कमज़ोर होंगे तो वही लोग नज़रें फेरने लगेंगे। इसलिए आज का पैग़ाम यही है कि परिस्थितियों को मजबूत बनाना ही इंसान की सबसे बड़ी ढाल है।

डॉ. मुश्ताक अहमद.

चेहरे पढ़िए जो हैं उदास...!

हर एक रिश्ते में रहने दो ये विश्वास,
हर वक़्त ज़ुबाँ पर रहने दो मिठास।
यह 'जीवन' चलता रहता हैं निरंतर,
यादों की गहराई में खूब हैं समुन्दर।

कभी सोचा 'खट्टी-मीठी' यादें कुरेदें,
जिंदगी को कुछ इस तरह से सहेज़ें।
अच्छाई जिंदा रहें बुराई भूली जाए,
यादों के सफर में सब खिलखिलाएं।

ज़िंदगी जीने का यहीं सही अन्दाज़,
करिए उन्हें मन से क्षमा नज़रन्दाज़।
वह चेहरे पढ़िए जो हो रहें हैं उदास,
खुशियाँ भरें जीवन में यहीं हैं खास।

संजय एम तराणेकर

नशा मुक्त भारत@2047-एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एनसीओआरडी की भूमिका-एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

"नशा समाज को खोखला कर देता है और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है।"
ड्रग्स की समस्या केवल एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहींहै,बल्कि पूरे समाज,सरकार और नागरिकों का सामूहिक दायित्व,होल ऑफ़ द गवर्नमेंट एप्रोच है-
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया महाराष्ट्र

भारत एक ऐसे युग से गुजर रहा है जहां विकास आधुनिकता और वैश्वीकरण की चुनौतियाँ समानांतर रूप से सामने खड़ी हैं। इनमें सबसे खतरनाक और जटिल समस्या मादक पदार्थों (ड्रग्स) की है। यह समस्या केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनियाँ के लिए एक गंभीरसंकट है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूंकि,ड्रग्स का अवैध कारोबार और उसका सेवन समाज की जड़ों को खोखला करता है, युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गहरा असर डालता है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने "नशा मुक्त भारत@2047" का लक्ष्य तय किया है, जो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक एक ऐसे भारत की परिकल्पना करता है जहाँ मादक पदार्थों का अवैध कारोबार और सेवन पूरी तरह समाप्त हो सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटी एफ), एनसीओआरडी (नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर for नर्कोर्ड मैकेनिज्म)और नार्कोटिक्स कंट्रोलब्यूरो (एनसीबी) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।ड्रग्स की समस्या केवल सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी है। ड्रग्स का पैसा आतंकी संगठनों और संगठित अपराध के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए यह खतरा और भी गंभीर है क्योंकि इसके पड़ोसी देशों में ड्रग्स उत्पादन और तस्करी का नेटवर्क सक्रिय है। "गोल्डन ट्राएंगल" और "गोल्डन क्रिसेंट" क्षेत्र से भारत में ड्रग्स की तस्करी लंबे समय से होती रही है।इसीलिए भारत की एंटी नार्कोटिक्स नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं,क्योंकि आगामी 16-17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एकऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसमें भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुख,अन्य सरकारी विभागों के हितधारक तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नशा मुक्त भारत @ 2047 के विज़न को ठोस आधार प्रदान करेगा और आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करेगा।भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन स्थापित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटी एफ)को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थों के खिलाफ एक संयुक्त तंत्र के रूप में गठित किया गया है।यह तंत्र आपूर्ति कम करने, मांग को नियंत्रित करने और नुकसान कम करने की नीति पर एक साथ काम करता है। एएनटीएफ का उद्देश्य केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में जागरूकता, शिक्षा और पुनर्वास को भी समान प्राथमिकता देना है। भारत के पीएम ने कई मौकों पर कहा है कि "नशा समाज को खोखला कर देता है और राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है।"इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री की अगुवाई में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

साथियों बात अगर हम सम्मेलन का विषयः संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी की करें तो इस द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय "संयुक्त संकल्प, साझा जिम्मेदारी" रखा गया है। यह विषय अपने आप में मादक पदार्थों की समस्या के समाधान का मूल मंत्र है। ड्रग्स की समस्या केवल एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज, सरकार और नागरिकों का सामूहिक दायित्व है। आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुलिस,सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक बल और कस्टम विभाग को मिलकर काम करना होगा। मांग कम करने के लिए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक संगठन अहम भूमिका निभाएँगे। नुकसान कम करने के लिए पुनर्वास केंद्र, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक सक्रिय योगदान देंगे। इस प्रकार यह समस्या एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है जिसे केवल साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत से ही सफल बनाया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम,2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में तकनीकी सत्रःआठ विशेष विमर्श की करें तो भविष्य का रोडमैप और नीति निर्धारण- 2047 तक नशा मुक्त भारत का विज़न पूरा करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर मंथन होगा।ये आठ सत्र न केवल समस्या की गहराई को समझने का अवसर देंगे बल्कि समाधान की दिशा में ठोस कदम भी सुझाएँगे।(1)सम्मेलन के दौरान आठ तकनीकी सत्र (टेक्निकल सेशयंस)आयोजित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा और रणनीति बनाना है।(2)ड्रग्स आपूर्ति श्रृंखला की रोकथाम- इसमें अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क, सीमा पार तस्करी, डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले कारोबार को रोकने की रणनीतियों पर चर्चा होगी। (3)ड्रग्स की मांग कम करने की रणनीति -शिक्षा, जागरूकता, युवाओं को खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर विचार किया जाएगा (4)नुकसान कम करने के उपाय-नशा करने वालों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसिक उपचार की दिशा में कदमों पर चर्चा होगी। (5) राष्ट्रीय सुरक्षा और ड्रग्स का संबंध-ड्रग्स से होने वाली आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। (6)कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाना- पुलिस, एनसीबी और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विमर्श होगा। (7) ड्रग्स और साइबर अपराध-डार्क वेब, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी। (8) अंतरराष्ट्रीय सहयोग- पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग, सूचना साझा करने और संयुक्त अभियानों पर विचार होगा।इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट-2024 जारी करेंगे। इस रिपोर्ट में बीते वर्ष में ड्रग्स की जब्ती, गिरफ़्तारियाँ, अवैध नेटवर्क का खुलासा और निवारक कदमों का विस्तृत विवरण होगा।साथ ही, श्री शाह ऑनलाइन ड्रग विनष्टीकरण अभियान (ड्रग डिस्पोजल कैंपेन) की शुरुआत करेंगे। यह अभियान एक अनोखी पहल होगी जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों का निपटान पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा।

साथियों बात अगर हम,आपूर्ति, मांग और नुकसान कम करने की रणनीति तथा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की करें तोमादक पदार्थों की समस्या को तीन स्तरों पर समझा जाता है-(1)आपूर्ति कम करना-यानी ड्रग्स की तस्करी, उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण।(2)मांग कम करना-यानी समाज में नशे की लत को रोकना और जागरूकता फैलाना(3) नुकसान कम करना-यानी नशे के शिकार लोगों का इलाज और पुनर्वास।

भारत ने इन तीनों स्तरों पर रणनीतियाँ अपनाई हैं।सीमा पार निगरानी बढ़ाना, ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कस्टम और पुलिस को मजबूत करना आपूर्ति रोकने की दिशा में अहम कदम हैं। मांग कम करने के लिए युवाओं में खेलकूद, योग, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं नुकसान कम करने के लिए पुनर्वास केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया जा रहा है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच-इस समस्या से निपटने के लिए केवल गृह मंत्रालय या एनसीबी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एक होल ऑफ़ द गवर्नमेंट एप्रोच की आवश्यकता है। यानी केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग-शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और विदेश मंत्रालय-सभी को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओस), नागरिक समाज और मीडिया की भी अहम भूमिका होगी। तभी यह लड़ाई व्यापक और सफल हो सकेगी।

साथियों बात अगर हम पहले सम्मेलन (अप्रैल 2023) और उसकी उपलब्धियों व राष्ट्रीय सुरक्षा और मादक पदार्थ को समझने की करें तो,अप्रैल 2023 में पहली बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटी एफ प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था।उस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें प्रमुख थे,(1) सभी राज्यों में विशेष एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट का गठन। (2)ड्रग्स जब्ती और तस्करी से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय डेटा बैंक की स्थापना। (3)सीमा पार से होने वाली तस्करी पर रोक के लिए सीमा सुरक्षा बलों और एनसीबी के संयुक्त अभियान। (4)युवाओं और छात्रों में जागरूकता के लिए स्कूल-विश्वविद्यालय आधारित अभियान। (5)जब्त मादक पदार्थों का समयबद्ध निपटान।इनमें से लगभग 70-75 प्रतिशत निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में विशेष एएनटीएफ, इकाइयाँ बन चुकी हैं, बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जब्ती हुई है, और राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स कीसूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक प्रभावी हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे सीमा पार तस्करी और ऑनलाइन ड्रग्स कारोबार में चुनौतियाँ बाकी हैं, जिन्हें इस दूसरे सम्मेलन में प्राथमिकता दी जाएगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किभारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का जो लक्ष्य तय किया है, वह कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामाजिक जागरूकता-इन सभी की समान आवश्यकता है।एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एनसी ओआरडी इस दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर चुके हैं। अब आवश्यकता है कि आगामी 16-17 सितंबर 2025 का सम्मेलन इस लड़ाई को नई गति और दिशा दे।यदि भारत "संयुक्त संकल्प और साझा जिम्मेदारी" के सिद्धांत पर आगे बढ़े, तो निश्चित ही 2047 तक एक नशा मुक्त भारत का सपना साकार हो सकता है। यह न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का संदेश होगा।

घर में जंची कॉपी, तब भी हुए फेल (आलेख : बादल सरोज)

आर एस एस के शताब्दी वर्ष आयोजन में अगस्त के दूसरे पखवाड़े में राजधानी में दो प्रमुख कार्यक्रम हुए। इसमें अंतिम सप्ताह में, 26 से 28 अगस्त को हुये तीन दिनी 'संवाद' को ठीक-ठाक से सजा-संवार कर पोसा और परोसा गया। फेसिअल से लेकर ब्लीचिंग, फाउंडेशन से लेकर टचिंग तक रूप सज्जा के हर चरण को खूब सावधानी से बरता गया। फ्लोर मैनेजमेंट से मीडिया मैनेजमेंट तक सब चुस्त था ; संघ की छवि को सुधारने के लिए ऐसे ही प्रश्न प्रायोजित किये गए थे, जिनके उत्तर व्यवस्थित तरीके से संयोजित किये जा सकें। इसमें तीनों दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। पाले पोसे, नत्थी बद्ध, दिखाऊ-छपाऊ मीडिया ने इसे पर्याप्त कवरेज भी दिया ; कईयों ने तो इसमें संभावनाएं और न जाने क्या-क्या तक देख भी लिया।

मगर इससे ठीक सप्ताह भर पहले, 19-20 अगस्त को दिल्ली में ही हुये ऐसे दूसरे संवाद के साथ यह नहीं हुआ। इसमें हुए विमर्श और संवाद को सूरज की रौशनी देखने का मौक़ा नहीं मिला, हुलसकर उसके बारे में बताने की बात तो दूर रही, हर संभव कोशिश की गयी कि उसमें जो हुआ है, उसे सार्वजनिक ना ही किया जाए। ऐसा होना भी था ; क्योंकि इसमें 11 साल में किये-धरे का मूल्यांकन किया जा रहा था ; संघ के स्वयंसेवक की अगुआई वाली सरकार की कॉपियां खुद अपने ही प्रोफेसर द्वारा जाँची जा रही थी और जो रिजल्ट निकल रहा था, वह किसी को दिखाने लायक नहीं था।

इसलिए कोई तीन सप्ताह तक इस मंथन बैठक की खबरें छुपाकर, दबाकर रखी गई और बाद में जब इंडियन एक्सप्रेस ने, उसमें हाजिर कोई दर्जन भर भागीदारों से जानकारी जुटा कर उसे छाप दिया, तो ज्यादातर मीडिया समूहों ने उसकी अनदेखी करना ही चुना ; मगर जो जानकारी थी, वह इतनी प्रामाणिक थी कि खुद संघ ने भी उसका खंडन-वंडन करने की हिम्मत नहीं जुटाई।

दो दिन तक एक बंद कमरे में हुई यह बैठक कोई छोटे-मोटे लोगों की नहीं थी। यह खुद संघ से जुड़े उसके 6 आनुषांगिक संगठनों की चिंतन बैठक थी – ये वही आनुषांगिक अधीनस्थ संगठन हैं, जिनके संघ-संबद्ध होने से स्वयं सरसंघचालक भागवत जी ने एक सप्ताह बाद इंकार किया था और दावा किया था कि आरएसएस के अधीनस्थ कोई संगठन नहीं है।

19-20 अगस्त को हुई इस बैठक का आयोजन और समन्वय भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन ने किया। उनके अलावा इसमें भारतीय किसान संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इनके अलावा खुद मोहन भागवत और उनके सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, सी.आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल लिमये और आलोक कुमार लगातार बैठक में उपस्थित रहे। संघ विचारक कहे जाने वाले एस गुरुमूर्ति, भाजपा के संगठन महासचिव बी.एल. संतोष, महासचिव अरुण सिंह तो थे ही, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी आमंत्रित अतिथियों में शामिल थे।

जाहिर है यह हाशिये पर बैठे लोगों का जमावड़ा नहीं था – नीति-निर्धारक माने जाने वाले महारथियों का समावेश था। इसमें मोदी सरकार के पिछले 11 साल के कामकाज की समीक्षा की जा रही थी और कॉपियां जांचने का काम भी किसी नौसिखिये के हाथ में नहीं था ; एक जमाने में भाजपा की नेतृत्व त्रयी के हिस्से रहे और जब तक वह प्रयागराज नहीं हुआ था, तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे डॉ. मुरली मनोहर जोशी खुद रिमोट हाथ में लिए स्लाइड-दर-स्लाइड दिखाते हुए नंबर दे रहे थे और हाथों-हाथ अनुत्तीर्ण होने का रिपोर्ट कार्ड भी थमाते जा रहे थे।

जोशी जी पूरी तैयारी के साथ आये थे ; मोदी सरकार की नीतियों की दिशा और उसके चलते हुई भारत की दुर्दशा पर उन्होने अपनी बात कोई 70 स्लाइड्स के साथ रखी। इन्हें रखते हुए उन्होंने उन नोबल सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी सहारा लिया, जिन्हे संघ और भाजपा का कुनबा गरियाता रहता है, शान्ति निकेतन में बने उनके घर को गिराने के मंसूबे बनाता रहता है। अमर्त्य सेन के कथन कि "यदि किसी राष्ट्र की आर्थिक सफलता का आकलन केवल आय से किया जाता है, तो कल्याण का महत्वपूर्ण लक्ष्य चूक जाता है।", को निष्कर्ष के रूप में रखते हुए उन्होने जो बातें कही, उन्हें पढ़कर भारत की संसद में घटी एक घटना की याद आई।

संसद में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों के निर्धारण में घोटाले और तब की सरकार की गलत बयानों का खंडन करते हुए प्रमोद महाजन एकदम ताजे तथ्यों और धारदार विश्लेषण के साथ भाषण झाड़े जा रहे थे और बीच-बीच में बगल की सीटों पर बैठे सीपीएम सांसद दीपंकर मुखर्जी की तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखते भी जा रहे थे ; उसकी वजह यह थी कि महाजन जो भी बोल रहे थे, वह एक दिन पहले पीपुल्स डेमोक्रेसी/लोकलहर में छपे दीपंकर दा के लेख को पढ़कर बोल रहे थे – यह बात बाद में खुद उन्होंने सेन्ट्रल हॉल में कामरेड दीपंकर को धन्यवाद देते हुए स्वीकार भी की।

ठीक यही काम आर्थिक दुर्दशा पर दी अपनी प्रस्तुति में मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिए गए प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी कर रहे थे ; वे सिर्फ अमर्त्य सेन का ही सहारा नहीं ले रहे थे, बल्कि जो आंकड़े और तथ्य रख रहे थे, उनके लिए भी वे ऐसा लगा, जैसे लोकलहर में छपे प्रभात पटनायक का ही सहारा ले रहे थे।

इन सभी 70 स्लाइड्स के विवरण में जाए बिना सिर्फ कुछ को ही दर्ज करें, तो संघ की इस बैठक में उन्होंने बताया :कि देश मे धन असमानता तेजी से बढ़ रही है और यह 2021 में, भारत की आबादी के सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के पास, कुल घरेलू संपत्ति का 65 प्रतिशत हिस्सा जमा हो गया है।

कि चौथी अर्थव्यवस्था बनने का दावा देश की जनता की स्थिति से मेल नहीं खाता है और विषम है। जिस जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की हांकी जा रही है, उसकी तुलना में भारतीय नागरिक की आमदनी 12 गुना कम है ; कि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2,878.5 डॉलर है, जबकि जापान की 33,955.7 डॉलर है।

कि सरकार का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि 'हम' कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहे हैं। हम, जो हमारे पास नहीं है, उसे पाने की योजना बनाते हैं। लेकिन जो हमारे पास है, उसकी रक्षा करने की योजना नहीं बनाते। जबकि हम ऐसे विदेशी सहयोग का स्वागत करते रहे, जो हमारे हितों और प्रतिष्ठा को कमजोर करते हैं। इस बात को और आगे बढाते हुए उन्होंने कहा कि विदेश पर अधिक निर्भर रहना भारत के हित में नहीं है।

कि तेजी से बढती आत्महत्यायें अच्छा संकेत नहीं है। उसमें भी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे युवाओं की आत्महत्याओं में बढ़त रोजगार और विकास के अलग तरह के संकट की सूचना है। 2018 में 1.34 लाख आत्महत्या हुई, जो 2022 में बढ़कर 1.70 लाख हो गईं। 2019 से 2021 के बीच 35,950 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं, 2018 से 2023 तक आई आई टी, आई आई एम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में 98 छात्रों ने जान दी।

कि भारत का उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जी ई आर) 32.7% है, जबकि 1995 में यह मात्र 5.5% था। हालांकि यह प्रगति है, लेकिन पोलैंड (75.3%) और जापान (64.6%) जैसे देशों से बहुत पीछे है।

कि भारत की 43.5% कार्यबल कृषि क्षेत्र में है, जबकि पोलैंड में यह 7.6% और जापान में मात्र 3% है। वहीं, भारत के उद्योग क्षेत्र में 25.03% और सेवा क्षेत्र में 31.5% लोग काम करते हैं। तुलना में जापान के आंकड़े क्रमशः 73.3% और 62.8% हैं।

कि भारत में केवल 23.9% लोग वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जबकि पोलैंड में यह संख्या 80.1% और जापान में 90.5% है।

जोशी जी जो कह रहे थे, उसमें कुछ भी नया नहीं है। देश इसे भुगत रहा है और अच्छी तरह जानता भी है। देश मोदी राज में महामारी की तरह बेलगाम होकर फैले पनपे उन कॉर्पोरेट के पूंजीवादी विकास के नियमों के हिसाब से भी असाधारण तेजी से हुए 'विकास' को भी जानता है, जिसे जोशी जी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में शामिल नहीं किया।

जैसा कि खबरें बताती हैं, यह सिर्फ मुरली मनोहर जोशी की राय भर नहीं थी। प्रस्तुति के अंत में खुद सर संघचालक ने 'जोशी जी सब कुछ बोल चुके हैं, अब और कुछ कहने को बाकी नहीं है', कहकर उनके आंकलन के साथ सहमति-सी जता दी।

हालांकि संघ के सरकार्यवाह होसबोले ने बाद में इस सबको एक सामान्य चर्चा करार देते हुए स्पष्टीकरण दिया है कि 'यह सरकार के कामकाज की आलोचना या समीक्षा नहीं है।' उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर यह मोदी राज की विफलताएं नहीं हैं, तो फिर यह किस ईश्वरी या आसुरी शक्ति का किया धरा है!! खैर, इस तरह की पर्दादारी ही तो इस कुनबे की अदाकारी है।

इस गोपनीय बैठक के अब गोपनीय नहीं रहे निष्कर्षों को अलग-अलग तरह से देखा गया है। कुछ इसे संघ की ओर से मोदी जुंडली पर बनाए जा रहे दबाब के रूप में देखते है। ये ये वे लोग है, जो संघ और मोदी के अद्वैत में द्वैत होने का भरम पाले हुए है और कभी-कभार दिखावे के लिए चमकाई जाने वाली फुलझड़ियों में धमाके की आस लगाये बैठे हैं। कुछ के मुताबिक़ यह विपक्ष के स्पेस को भी खुद ही भरने की संघ की कलाकारी है, जिसे पहले कभी स्वदेशी जागरण मंच के नाम पर, तो बीच में कभी-कभार भारतीय मजदूर संघ के नाम पर छोटी-मोटी जमावटें करके, सीमित शोर-शराबे के साथ मंचित किया जाता रहा है।

कुछ हद तक यह इस काम को करती भी है। मगर असल बात यह है कि 'विकास' इस कदर मुंह के बल गिरा और जनता में क्षोभ और आक्रोश इतना बढ़ा है कि अब अन्तःपुर में भी बेचैनी और घबराहट होने लगी है। ऐसी गोपनीय कोशिशें अब उजागर हो गयी दिवालिया नीतियों के मजबूत जाल में उलझन- सुलझन की राह तलाशने की फ़क्रि में पड़ी हुई हैं। वे यह भूल रहे है कि मूल समस्या सिर्फ व्यवहार में नहीं है, उस विचार में है, जो संघ का विचार है। विदेशी कार्पोरेट से गलबहियां करके देश में कार्पोरेटी हिंदुत्व को मजबूत करते हुए इसी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है, जिस पर पहुँचने पर मंथन बैठक में टसुये बहाए जा रहे हैं।

शंघाई कोऑपरेशन की बैठक से लौटकर, ट्रंप के संदेश को लपककर और ब्रिक्स की शिखर वार्ता में अपनी जगह एस जयशंकर को भेज कर मोदी सरकार ने साफ़ कर दिया है कि साम्राज्यवाद की दुम से अलग होने इच्छा और इच्छाशक्ति दोनों ही उसमें नहीं हैं।

भारतीय संस्कारों की सरिता, महान परंपरा : विदेशों में बसे भारतीयों के दिल में उनके पुरखों द्वारा भारत से लाए लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्य, संस्कारों की सरिता हमेशा जीवंत रहती है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
गोंदिया महाराष्ट्र

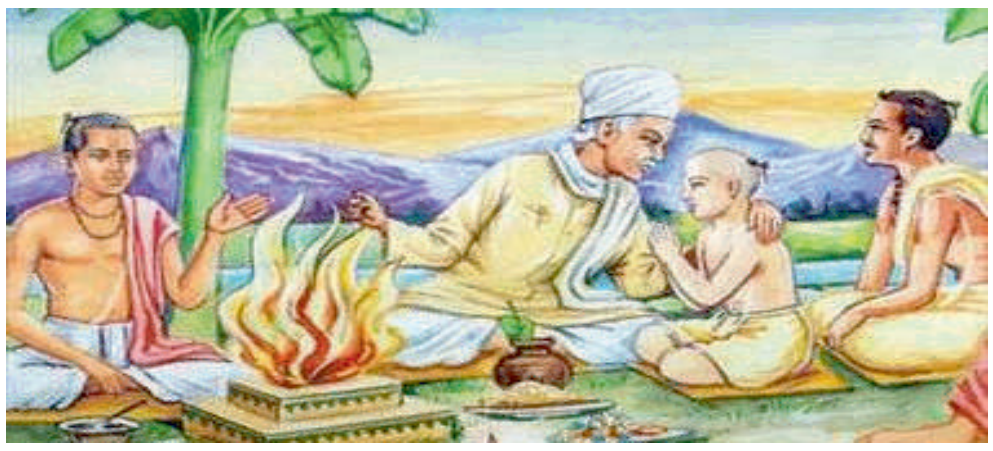

वैश्विक स्तरपर आज भारतीय संस्कारों की सरिता, महान परंपरा, भारतीय सभ्यता, वैचारिक अधिष्ठान रूपी आवाज़ अब केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, यह विश्व भर में फैल रहे हैं और पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं इसका एहसास हमें अब होने लगा है, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी चैनलों पर भारत के पीएम के अनेक विदेश दौरों में देखा कि किस तरह वहां पीढ़ियों से बसें भारतीय मूल के लोगों के दिल में उनके पुरखों द्वारा भारत से लाए लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्यों से संस्कारों की सरिता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा जब वे भारतीय पीएम के प्रति इतनी उत्सुकता और अपनी पुरखों की मिट्टी से कोई उनके देश आता है तो उनके दिल के कोने से करोड़ों खुशियों के फव्वारे होते हैं यह हम देखते आ रहे हैं

साथियों बात अगर हम भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषा की करें तो यह ऐसा व्यक्ति जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता है/करती है। इन लोगों के पास उसी देश का पासपोर्ट होता है। चूंकि इन लोगों के पास विदेशी पासपोर्ट होता है।

साथियों बात अगर हम भारतीय मूल के व्यक्तियों की गाथा की करें तो कल्पना चावला कमला हैरिस के काम और नाम तो हम जानते ही हैं इसके अलावा,अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से पहले एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किए गए उन 34 अप्रवासियों में से हैं, जिन्होंने अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत किया है। गोपीनाथ और लुल्ला न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की तरफ से नामित '2021 ग्रेट इमिग्रेंट्स (महान प्रवासी) की लिस्ट में शामिल हैं।ये एक गैर सरकारी संगठन है।विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारतीय समुदाय का दबदबा कायम रखते हुए भारतीय मूल के छह किशोरों ने अमेरिका का प्रतिष्ठित डेविडसन फेलो स्कॉलरशिप हासिल कर ली है। सिंगापुर में भारतीय मूल के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव शक्तिबालन बालथंडौथम को अपने लीवर का एक हिस्सा एक साल की बच्ची को दान करने के लिए ₹द स्ट्रेट्स टाइम्स सिंगापुरियन ऑफ द ईयर 2021₹ का पुरस्कार मिला है, जिससे वह पहले कभी नहीं मिले थे। अमेरिका में मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए आयोजित होने वाली एक प्रमुख विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में भारतीय मूल के बच्चों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता के पांच विजेताओं में भारतीय मूल के चार बच्चे शामिल हैं, जिसमें 14 वर्षीय भारतीय मूल के लड़के ने प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है।

साथियों बात अगर हम भारतीय संस्कृति की करें तो भारतीय संस्कृति व सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। जीने की कला हो, विज्ञान हो या राजनीति का क्षेत्र भारतीय संस्कृति का सदैव विशेष स्थान रहा है।अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ-साथ नष्ट होती रही हैं किंतु भारत की संस्कृति व सभ्यता आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर-अमर बनी हुई है। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिये प्रसिद्ध देश है। ये विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है।

भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व अच्छे शिष्टाचार, तहज़ीब, सभ्य संवाद, धार्मिक संस्कार, मान्यताएँ और मूल्य आदि हैं। अब जबकि हरेक की जीवन शैली आधुनिक हो रही है, भारतीय लोग आज भी अपनी परंपरा और मूल्यों को बनाए हुए हैं। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश, भारत बनाया है। अपनी खुद की संस्कृति और परंपरा का अनुसरण करने के द्वारा भारत में लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं।

साथियों बात अगर हम भारतीय संस्कृति के प्रमुख विशेषताओं की करें तो ,(1)आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय, (2)- सम्मानता- सम्भाव का होना,(3)- अनेकता में एकता की शक्ति , (4)- भारत माता का हित एवं उन्नति-तरक्की की सोच (5)- ग्रहणशीलता- उत्सवों की प्रांगणता (6)- शास्त्रों की महानता, व उपयोगिता, (7)- विविधता- प्राचीनता (8)-भावनाएँ-विश्वास-परम्पराएं, (9)- गतिशीलता- निरंतरता,(10)- लचीलापन एवं सहिष्णुता,(11)- वसुधैव कुटुम्बकम्की भावना,(12)- जीवों का संरक्षण, सभी प्राणियों के हितैषी, (13)- लोकहित और विश्व-कल्याण, (14)- पर्यावरण संरक्षण,(15)- नारियों का सम्मान व उत्थान।

साथियों बात अगर हम माननीय पीएम द्वाराएक कार्यक्रम में संबोधन की करें तो पीआईबी के अनुसार उन्होंने कहा, एक भारतीय दुनिया में कहीं भी रहे, कितनी ही पीढ़ियों तक रहे, उसकी भारतीयता, उसकी भारत के प्रति निष्ठा, लेश मात्र भी कम नहीं होती। वो भारतीय जिस देश में रहता है पूरी लगन और ईमानदारी से उस देश की भी सेवा करता है। जो लोकतांत्रिक मूल्य, जो कर्तव्यों का ऐहसास उसके पुरखे भारत से ले गए होते हैं, वो उसके दिल के कोने में हमेशा जीवंत रहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत एक राष्ट्र होने के साथ ही एकमहान परंपरा है, एक वैचारिक अधिष्ठान है, एक संस्कार की सरिता है।भारत वो शीर्ष चिंतन है-जो 'वसुधैव कुटुंबकम' की बात करता है। भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। भारत अपने साथ सम्पूर्ण मानवता के, पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करता है। इसीलिए, कनाडा या किसी भी और देश में जब भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित कोई सनातन मंदिर खड़ा होता है, तो वो उस देश के मूल्यों को भी समृद्ध करता है। इसलिए, आप कनाडा में भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, तो उसमें लोकतन्त्र की साझी विरासत का भी सेलिब्रेशन होता है। और इसलिए, मैं मानता हूँ, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये सेलिब्रेशन कनाडा के लोगों को भी भारत को और नजदीक से देखने समझने का अवसर देगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारतीय संस्कारों की सरिता, महान परंपरा विदेशों में बसे भारतीयों के दिल में उनके पुरखों द्वारा भारत से लाए लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्यों संस्कारों की सरिता हमेशा जीवंत पर रहती है तथा

यामाहा XSR 155 टेस्टिंग के दौरान दिखी, जल्द होगी भारत में लॉन्च, कैसे होंगे फीचर्स और कितनी हो सकती है कीमत

Yamaha XSR 155 यामाहा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में स्कूटर और मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता जल्द ही नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इसे टेसटिंग के दौरान देखा गया है। यामाहा की नई मोटरसाइकिल कब तक लॉन्च हो सकती है। आइए जानते हैं।

नईदिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में हर महीने दो पहिया वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें से मोटरसाइकिल सेगमेंट का बड़ा योगदान होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यामाहा की ओर से जल्द ही नई मोटरसाइकिल के तौर पर Yamaha XSR 155 को लॉन्च किया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल को कब तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Yamaha XSR 155 होगी लॉन्च

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यामाहा की ओर से नई मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी निर्माता की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों के दौरान इसे लॉन्च किया जाएगा।

क्या मिली जानकारी

यामाहा की नई मोटरसाइकिल को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी मिली है। लॉन्च से पहले निर्माता की ओर से इसे टेस्ट किया जा रहा है। इसी दौरान इस मोटरसाइकिल को देखा गया है। टेस्ट के दौरान देखी गई यूनिट पूरी तरह से ढंकी हुई थी। लेकिन इसे नियो रेट्रो डिजाइन के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

कैसे होंगे फीचर्स

निर्माता की ओर से लॉन्च के समय ही इसके सभी फीचर्स की जानकारी दी जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि इसमें 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी लाइट्स, ड्यूल चैनल एबीएस, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल सीट जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन

यामाहा की ओर से इस बाइक में 150 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन ही दिया जा सकता है। जिससे इसे 18.5 पीएस की पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसमें पांच स्पीड ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा।

कब होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी इस बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में 11 नवंबर को लॉन्च किया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

भारतीय बाजार में यामाहा की नई मोटरसाइकिल को भी 150 सीसी क्षमता वाले सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। इस मोटरसाइकिल को सीधे तौर पर Yamaha FZ, Bajaj Pulsar, TVS Apache, Hero और Honda की मोटरसाइकिल से चुनौती मिलेगी।

वोक्सवैगन की गाड़ियों पर जबरदस्त डिस्काउंट, 3 लाख रुपये तक की दी जा रही छूट

फेस्टिव सीजन में Volkswagen इंडिया ने सितंबर 2025 में Tiguan Taigun और Virtus जैसे चुनिंदा मॉडलों पर भारी छूट का एलान किया है। Tiguan पर 3 लाख रुपये तक की छूट है जबकि Taigun पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। Virtus के 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले टॉपलाइन वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

नईदिल्ली। फेस्टिव सीजन में कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Volkswagen इंडिया ने सितंबर 2025 में अपने चुनिंदा मॉडलों पर भारी छूट का एलान किया है। Tiguan, Taigun और Virtus पर मिलने वाले डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स के चलते ये गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि Volkswagen की गाड़ियों पर सितंबर 2025 में कितना डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है?

Volkswagen Tiguan पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 3 लाख रुपये तक की छूट

अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई नई जेनरेशन Volkswagen Tiguan के R Line वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपये रखी गई थी। इस फ्लैगशिप SUV पर इस महीने ग्राहकों को 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इसे 204hp की पावर जनरेट करने वाले 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ऑफर करती है। यह पावर चारों पहियों तक पहुंचाता है, जिससे SUV का परफॉर्मेंस और भी दमदार हो जाता है।

Volkswagen Taigun पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 1.55 लाख रुपये तक की छूट

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में पॉपुलर Volkswagen Taigun पर भी अच्छा ऑफर दिया जा रहा है। टॉपलाइन 1.0 TSI AT वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। हाईलाइन वेरिएंट पर 1 लाख रुपये और GT Line वेरिएंट्स 1.1 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके बेस कम्फर्टलाइन वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अब सिर्फ 10.99 लाख रुपये रखी गई है, जो एक्स-शोरूम प्राइस से 80,000 रुपये कम है। वहीं, GT 1.5 TSI (MT और DSG दोनों) पर 1.55 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है।

Volkswagen Virtus पर डिस्काउंट

डिस्काउंट ऑफर: 1.5 लाख रुपये तक की छूट

Volkswagen Virtus के 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वाले टॉपलाइन वेरिएंट पर 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। वहीं, कम्फर्टलाइन वेरिएंट की कीमत इस महीने 11.56 लाख रुपये से घटाकर 10.54 लाख रुपये कर दी गई है। Virtus के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वेरिएंट्स पर एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस के साथ करीब 90,000 रुपये तक की बचत संभव है। खास बात यह है कि 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट्स की कीमत में अस्थायी तौर पर 35,000 से 40,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

डिस्क्लेमर: यह डिस्काउंट्स डीलरशिप, स्टॉक अवेलेबिलिटी और जगह के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको खरीदारों को सलाह दी जाती है कि आप अपने नजदीकी Volkswagen शोरूम पर जाकर सही ऑफर्स की जानकारी जरूर लें।

मारुति विक्टीरीज वर्सेज वॉक्सवेगन टाइगुन : फीचर्स, इंजन और माइलेज में कितना अंतर

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को देश में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। मारुति की ओर से हाल में ही विक्टोरिस को लॉन्च किया गया है। वहीं इस सेगमेंट में फॉक्सवैगन की ओर से ताइगुन को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। फीचर्स इंजन माइलेज और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

नईदिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Maruti Victoris को लॉन्च किया गया है। बाजार में इस एसयूवी का सीधा मुकाबला Volkswagen Taigun के साथ भी होगा। इंजन, माइलेज, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun इंजन

मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी को हाल में ही लॉन्च किया गया है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्प के साथ भी ऑफर किया जाता है।

वहीं Volkswagen Taigun में इंजन के दो विकल्प मिलते हैं। जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल TSI इंजन से 150 पीएस पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। दूसरे पेट्रोल इंजन के तौर पर एक लीटर TSI इंजन मिलता है जिससे 115 पीएस की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इन विकल्पों के साथ छह स्पीड मैनुअल, छह स्पीड ऑटोमैटिक और सात स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं।

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun माइलेज

मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी एक लीटर में 21.18 किलोमीटर तक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ चलाया जा सकता है। इसके ऑटोमैटिक वेरिएंट को एक लीटर में 21.06 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

वहीं Volkswagen Taigun को भी एक लीटर पेट्रोल में 18.46 से 19.89 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

Maruti Victoris Vs Volkswagn Taigun फीचर्स

मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्बी एटमॉस सिस्टम, जेस्टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्सा ऑटो वॉयस असिस्टेंट, 35 से ज्यादा कनेक्टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्वर रंग का उपयोग किया गया है।

वहीं Volkswagen Taigun में 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, इनफिनिटी एलईडी टेल लैंप, शॉर्क फिन एंटीना, ड्यूल टोन एक्सटीरियर और इंटीरियर, 385 लीटर की क्षमता का बूट स्पेस, सिंगल पेन सनरूफ, एंबिएंट लाइट्स, लेदर सीट्स, ऑटो एसी, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, की-लैस एंट्री, फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज, रिमोट इंजन स्टार्ट के साथ स्मार्ट की, रियर एसी वेंट्स, रियर वाइपर और वॉशर, टिल्ट स्टेयरिंग व्हील, आईएसजी, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, आठ इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑडियो सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun सुरक्षा

मारुति की ओर से विक्टोरिस एसयूवी को कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Volkswagen Taigun को भी सुरक्षा के मामले में क्रैश टेस्ट के बाद पूरे पांच अंक मिल चुके हैं। इस एसयूवी को Global NCAP की ओर से व्यस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिए में छह एयरबैग, ईबीडी, ईएससी, वीएसएम, हिल स्टार्ट कंट्रोल, टीपीएमएस, रियर डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स, थ्री पाइंट सीटबेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, ईएसएस, ऑटो हेडलैंप, हेडलैंप एस्कॉर्ट, पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

Maruti Victoris Vs Volkswagen Taigun कीमत

मारुति की ओर से अभी विक्टोरिस की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत की शुरुआत भी 11 लाख रुपये के आस पास से हो सकती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत भी 20 लाख रुपये तक हो सकती है।

वहीं Volkswagen Taigun की कीमत 10.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से 19.58 लाख रुपये एक्स शोरूम तक है।

समीक्षा

मारुति की ओर से विक्टोरिस को नई एसयूवी के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन अभी उसकी कीमत की सही जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही इस एसयूवी की माइलेज का टेस्ट भी रियल टाइम में नहीं किया गया है।

वहीं दूसरी ओर फॉक्सवैगन की ताइगुन को हमने चलाकर भी देखा है और उसकी कीमत की सही जानकारी भी सार्वजनिक है। अगर आपको ज्यादा सुरक्षित और दमदार इंजन वाली एसयूवी चाहिए तो फिर आप फॉक्सवैगन की ताइगुन को चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस सेगमेंट में सीएनजी के साथ एसयूवी चाहिए तो फिर आप थोड़ा समय रुक कर मारुति विक्टोरिस का चुनाव कर सकते हैं।

कैसी है स्कोडा की सबसे छोटी एसयूवी, क्या खरीदने में होगी समझदारी?

स्कोडा की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काइलैक की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस एसयूवी को हमें कुछ दिनों तक चलाने का मौका मिला। इस दौरान हमने इसे कई कसौटियों पर परखने की कोशिश की। क्या इंजन फीचर्स माइलेज और आराम के मामले में यह एसयूवी बेहतर है। या फिर किसी दूसरे विकल्प को चुनना बेहतर होगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा विकल्प मिलते हैं। कई निर्माता इस सेगमेंट में बेहतरीन फीचर्स के साथ ही दमदार इंजन वाली एसयूवी की बिक्री करती हैं। स्कोडा की ओर से भी इस सेगमेंट में काइलैक की बिक्री की जाती है। कुछ दिनों तक हमें इस एसयूवी के ऑटोमैटिक वेरिएंट को चलाने का मौका मिला। इस दौरान हमने इसे इंजन, फीचर्स, ड्राइविंग के मामले में कई कसौटियों पर परखने की कोशिश की। जिसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है या नहीं।

Skoda Kylaq कैसी है

स्कोडा की ओर से सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर काइलैक को भारत में ऑफर किया जा रहा है। लॉन्च के बाद से ही इस एसयूवी को कई लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि न तो इसमें कनेक्टिड लाइट्स मिलती हैं लेकिन सामने की ओर से इसमें चौड़ी ग्रिल मिलती है। एलईडी लाइट्स मिलती हैं। रियर में भी बॉक्सी और क्लीन लुक के साथ इसे ऑफर किया गया है। जो स्कोडा की बाकी एसयूवी में भी देखने को मिलता है। एसयूवी में सामने से लेकर पीछे तक क्लैडिंग दी गई हैं जो इसे किसी बड़ी एसयूवी की तरह दिखाने की कोशिश करती हैं।

कैसा है इंटीरियर

एसयूवी के इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम दी गई है। जिसमें ज्यादा जगह पर काले रंग का उपयोग किया गया है। साथ में हरे रंग के इंसर्ट्स भी दिए गए हैं जो काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि इसके एसी वेंट्स, एसी कंट्रोल पैनल, स्टेयरिंग व्हील और सेंट्रल कंसोल को इससे बड़ी एसयूवी कुशाक से लेकर दिए जैसे लगते हैं। इसके फ्रंट में आर्म रेस्ट दिया गया है जो लंबी ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को ज्यादा आराम देने का काम करता है। हालांकि इसमें दी गई लाइट के बटन की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एसयूवी की फ्रंट सीट में वेंटिलेशन जैसे फीचर को दिया है जो गर्मियों के मौसम में काफी आराम देता है। इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिलता है जो इस सेगमेंट की एसयूवी में कम ही देखने को मिलता है। ड्राइविंग सीट भी इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट की जा सकती है जो आपको प्रीमियम फील देने का काम कर सकता है और अपनी पसंद की पोजिशन में बैठकर कार को चलाना आसान बना देता है। एसयूवी में 360 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जिसमें आसानी से दो से तीन बड़ी ट्रॉली बैग, डफल बैग में सामान को रखा जा सकता है। बूट स्पेस में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि छोटे बैग को सही से रखने के लिए हुक दिए गए हैं और रात या कम रोशनी के लिए इसमें बूट लैंप भी मिलेगी।

कैसे हैं फीचर्स

एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स दिए हैं। जिनमें एलईडी लाइट्स, कॉर्नरिंग लैंप, फ्रंट के दरवाजों से की-लैस एंट्री, वायरलैस चार्जर, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, आठ इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सही फोकस के साथ इंटीरियर लाइट्स, बड़े ग्रैब हैंडल, फ्रंट में वेंटिलेटिड सीट्स, आर्मरेस्ट, 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, छह स्पीकर ऑडियो सिस्टम, सिंगल सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितनी है सुरक्षित

स्कोडा की काइलैक में सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएससी, टीपीएमएस, हिल होल्ड कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा को दिया गया है। हालांकि इसमें दिए गए रियर पार्किंग कैमरा की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर को भी देकर स्कोडा इसे और बेहतर विकल्प बना सकती है। लेकिन फिर भी इसको क्रैश टेस्ट के बाद पूरे पांच अंकों की सेफ्टी रेटिंग मिलती है।

कितना दमदार इंजन

स्कोडा काइलैक में निर्माता की ओर से एक लीटर का टर्बो इंजन ही दिया जाता है। इंजन से एसयूवी को 115 पीएस की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। हमें इस एसयूवी के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट को चलाने का मौका मिला। जिसकी गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ है। छोटे इंजन के साथ भी इंजन से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलता। इंजन की आवाज और वाइब्रेशन भी केबिन में नहीं आती जो काफी अच्छी बात है। ट्रैफिक के साथ ही खुली सड़कों पर भी इसे चलाना काफी आसान है। कम स्पीड के साथ ही तेज स्पीड में भी इस पर कंट्रोल रखना काफी आसान है। हाइवे पर भी इसमें ओवरटेक करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती।

फाइनल वर्डिक्ट

आपको बेहद सुरक्षित एसयूवी में से एक की तलाश है। बाजार में मिलने वाले विकल्पों से हटकर कुछ चाहते हैं। ऐसे गाड़ी चाहिए जिसमें कुछ काफी ज्यादा और न ही कम फीचर्स मिलें। छोटा लेकिन दमदार और अच्छी हैंडलिंग वाली एसयूवी चाहिए तो आप स्कोडा की काइलैक को आसानी से चुन सकते हैं।

आपको ऐसी एसयूवी चाहिए जिसमें पैनोरमिक सनरूफ हो, ज्यादा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, ज्यादा बड़ा इंजन हो, ड्राइविंग के मोड्स हों, ड्यूल जोन ऑटोमैटिक एसी हो, रियर में भी वेंटिलेटिड सीट्स हों, 360 डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स हों तो फिर आप किसी और विकल्प का चुन सकते हैं।

"पानी से नहीं, नीतियों से हारी ज़िंदगी"

डॉ सत्यवान सौरभ

बार-बार दोहराई गई त्रासदी, बाढ़ प्रबंधन क्यों है अधूरा सपना?

हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्य बार-बार बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं, लेकिन हर बार नुकसान झेलने के बावजूद स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल नज़र नहीं आती। 2023 की बाढ़ के बाद भी करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियों की सफाई, नालों की निकासी और जल प्रबंधन की योजनाएं अधूरी पड़ी रहीं। नतीजा यह कि 2025 में एक बार फिर लाखों किसान अपनी मेहनत की फसल डूबते देख मजबूर हुए। सवाल यह है कि जब बाढ़ का खतरा बार-बार दस्तक देता है तो हमारी नीतियां क्यों स्थायी हल नहीं तलाश पातीं?

- डॉ सत्यवान सौरभ

हरियाणा में 2025 की बाढ़ कोई अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा नहीं थी। यह वही त्रासदी है, जिसकी पुनरावृत्ति राज्य 1978, 1988, 1995, 2010 और हाल ही में 2023 में झेल चुका है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केवल पिछले दो वर्षों में 657 करोड़ रुपये बाढ़ प्रबंधन पर खर्च किए गए, फिर भी इक्कीस जिलों के सैकड़ों गांव पानी में डूबे रहे, साढ़े चार लाख से अधिक किसानों की छब्बीस लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, हजारों परिवार बेघर हो गए और तेरह लोगों की जान चली गई। हर बार यह सवाल उठता है कि आखिर सरकारें और तंत्र क्यों एक ही गलती बार-बार दोहराते हैं और पिछले अनुभवों से सबक क्यों नहीं लेते।

बाढ़ कोई अचानक आई विपत्ति नहीं है, बल्कि एक अनुमानित और बार-बार आने वाला खतरा है। नदियों का उफान, बरसाती नालों का रुख बदलना और निकासी व्यवस्था का ध्वस्त होना ऐसी समस्याएं हैं, जो पहले से ज्ञात हैं और जिनका समाधान वर्षों से टलता आ रहा है। 2023 की बाढ़ के बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे कि स्थायी समाधान के लिए ड्रेनेज सुधार, तटबंध मजबूत करने और नालों की गहराई बढ़ाने का काम प्राथमिकता पर होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि अधिकांश योजनाएं अधूरी रहीं और जो शुरू हुईं वे भ्रष्टाचार या लापरवाही की भेंट चढ़ गईं।

इस अव्यवस्था का सबसे गहरा असर किसानों पर पड़ा है। खरीफ सीजन की धान, बाजरा और गन्ने जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। औसतन एक किसान को प्रति एकड़ पंद्रह से बीस हजार रुपये का नुकसान हुआ। इसके साथ ही पशुधन की मौतें, घरों के ढहने और बुनियादी ढांचे के टूटने से हालात और बिगड़ गए। उद्योग जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। अंबाला और यमुनानगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों और गोदामों में पानी भर गया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ और हजारों मजदूर रोजगार से वंचित हो गए।

इस स्थिति के पीछे प्रशासनिक लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। हरियाणा सरकार के पास न तो गांव-स्तरीय निकासी योजना है और न ही कोई स्थायी रणनीति। मानसून से पहले नालों की सफाई करने की बजाय दिखावटी काम किए जाते हैं। कई जगह ड्रेनेज सिस्टम सालों से जाम पड़े हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नदियों और नालों का प्रवाह जस का तस है। इसके अलावा सिंचाई विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल का अभाव स्थिति को और गंभीर बना देता है। हर विभाग अपने-अपने दायरे में काम करता है, लेकिन समन्वय के अभाव में कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता।

जल प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि बाढ़ पर काबू पाने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक रणनीति बनाना अनिवार्य है। डॉ. शिव सिंह राठ जैसे विशेषज्ञ स्पष्ट कहते हैं कि नदियों की नियमित ड्रेजिंग, बरसाती नालों का वैज्ञानिक पुनर्निर्माण और गांव स्तर तक जल निकासी प्रणाली का निर्माण ही स्थायी समाधान दे सकता है। पर्यावरणविदों का भी यही तर्क है कि नदियों के तटों पर अनियंत्रित अतिक्रमण और अवैध निर्माण बाढ़ की विभीषिका को और बढ़ा देते हैं। जब तक नदियों को उनका प्राकृतिक बहाव नहीं लौटाया जाएगा, तब तक यह त्रासदी बार-बार लौटकर आती रहेगी।

किसानों और आम लोगों की पीड़ा आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। हजारों परिवार महीनों तक राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, महिलाओं और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ती है और मजदूर वर्ग बेरोज़गारी का शिकार हो जाता है। इस बार भी छह हजार से ज्यादा गांव पानी में डूबे और करीब अट्ठाईस सौ लोग विस्थापित हुए। कल्पना कीजिए, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घर-बार से उजड़ते हैं, तो उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति किस हद तक डगमगा जाती होगी।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2010 और 2023 जैसी बड़ी बाढ़ें आ चुकी थीं, तो 2025 में वही गलती दोहराने का औचित्य क्या था। असल कारण साफ हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने इस मुद्दे को कभी चुनावी एजेंडा नहीं बनने दिया। सरकारों का दृष्टिकोण हमेशा अल्पकालिक रहा। हर साल राहत और पुनर्वास पर खर्च होता रहा, लेकिन स्थायी संरचनाओं पर निवेश नहीं हुआ। इसके साथ ही भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी ने हालात और बदतर कर दिए।

अगर सचमुच स्थायी समाधान चाहिए तो राज्य को ठोस कदम उठाने होंगे। एक स्वतंत्र नदी प्रबंधन आयोग का गठन करना होगा, जो नदियों और नालों की सफाई, तटबंध निर्माण और निगरानी जैसे काम नियमित रूप से करे। हर पंचायत स्तर पर ड्रेनेज योजना तैयार की जानी चाहिए और उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित होना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पूर्वानुमान और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना होगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी से नालों की सफाई और तटबंधों की देखरेख सुनिश्चित करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि राहत पैकेज पर अरबों रुपये खर्च करने के बजाय स्थायी ढांचे और संरचनाओं पर निवेश किया जाना चाहिए।

दरअसल बाढ़ केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानवीय लापरवाही और नीतिगत असफलता का परिणाम भी है। हरियाणा ने नौ बार बाढ़ झेली, लेकिन हर बार केवल आंकड़े गिनने और वादे करने तक ही बात सीमित रही। किसानों की पीड़ा, उद्योगों का नुकसान और विस्थापित परिवारों की त्रासदी हमें यह बताती है कि अब आधे-अधूरे उपायों से काम नहीं चलेगा। सरकार और समाज को मिलकर व्यापक, वैज्ञानिक और दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन नीति अपनानी ही होगी, वरना 2027 या 2030 में फिर यही खबर पढ़नी पड़ेगी— "एक और बाढ़, एक और नुकसान और एक और अधूरा वादा।"

हिन्दी दिवस : मातृभाषा का सम्मान

विजय गर्ग

भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तभी से हर वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और भाषाई गौरव का प्रतीक है।

हिन्दी की महत्ता

हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। यह जनमानस को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी है। हिन्दी साहित्य, कविता, कहानी, उपन्यास और पत्रकारिता ने न केवल भारतीय समाज को दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी हिन्दी का योगदान अविस्मरणीय रहा।

वर्तमान परिदृश्य

आज के वैश्विक युग में अंग्रेज़ी का महत्व बढ़ा है, परन्तु हिन्दी का दायरा भी लगातार फैल रहा है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को आधिकारिक दर्जा दिलाने के प्रयास जारी हैं। डिजिटल प्लेटफार्म, सोशल मीडिया और सिनेमा ने हिन्दी को और सशक्त बनाया है।

हमारी जिम्मेदारी

हिन्दी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि मातृभाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम चाहे किसी भी भाषा में दक्ष हों, हिन्दी को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। विद्यालयों, महाविद्यालयों, दफ्तरों और दैनिक जीवन में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना ही इसका वास्तविक सम्मान है।

निष्कर्ष

हिन्दी दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि संकल्प का दिन है। संकल्प इस बात का कि हम अपनी भाषा की समृद्धि और उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। हिन्दी हमारी पहचान है और इसका संरक्षण व प्रचार-प्रसार हम सबकी जिम्मेदारी है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

भौतिकी से पहले, गणित था: मानव इतिहास के माध्यम से यात्रा

विजय गर्ग

भौतिकी होने से पहले, गणित था। यह कथन सटीक है। गणित एक मौलिक भाषा और उपकरण है जिसे हमारे आसपास की दुनिया का वर्णन और समझने के लिए विकसित किया गया था। इसका इतिहास मानव सभ्यता में बहुत पीछे है, अध्ययन के एक अलग क्षेत्र के रूप में भौतिकी की औपचारिक स्थापना से पहले। संख्याओं का डॉनः प्री-फिजिक्स गणित प्रारंभिक मनुष्यों ने वैज्ञानिक क्रांति से बहुत पहले व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए गणितीय अवधारणाओं का उपयोग किया। गिनती और बुनियादी अंकगणित के साक्ष्य प्रागैतिहासिक कलाकृतियों में पाए जा सकते हैं, जैसे कि टैली स्टिक। इनका उपयोग पशुधन, चंद्र चक्र या व्यापार वस्तुओं जैसी चीजों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था।

प्राचीन सभ्यताएँः मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी में सभ्यताओं ने व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए परिष्कृत गणितीय प्रणालियाँ विकसित कीं। मेसोपोटामियंस ने एक आधार -60 अंक प्रणाली का उपयोग किया (जिसे हम आज भी अपने समय और कोणों के माप में देखते हैं), और मिस्रियों ने भूमि सर्वेक्षण और बड़े पैमाने पर पिरामिड के निर्माण के लिए ज्यामिति विकसित की। गणित के ये शुरुआती उपयोग भौतिकी के औपचारिक अध्ययन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन समाजों के विकास के लिए आवश्यक थे। यूनानीः व्यावहारिकता से लेकर दर्शन तक प्राचीन यूनानियों ने गणित को विशुद्ध रूप से व्यावहारिक उपकरण से दार्शनिक जांच के क्षेत्र में ऊंचा किया। यूक्लिड के तत्व इस अवधि का एक आधारशिला है, जो ज्यामिति के लिए एक कठोर, स्वयंसिद्ध दृष्टिकोण स्थापित करता है। जबकि अरस्तू और आर्किमिडीज जैसे ग्रीक विचारकों ने अध्ययन किया कि अब हम भौतिकी को क्या कहते हैं, उनका काम अक्सर एक व्यापक दार्शनिक और गणितीय संदर्भ के भीतर तैयार किया गया था, न कि एक अलग, प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में। लीवर और हाइड्रोस्टैटिक्स पर उनका काम ज्यामितीय सिद्धांतों में गहराई से निहित था। भौतिकी का जन्मः गणित और प्रयोग को एकजुट करना दर्शन और शुद्ध गणित से भौतिकी का सही पृथक्करण वैज्ञानिक क्रांति के दौरान शुरू हुआ। गैलीलियो गैलीली को अक्सर ₹आधुनिक भौतिकी का पिता₹ माना जाता है क्योंकि वह अनुभवजन्य अवलोकन और प्रयोग के साथ गणितीय मॉडलों को व्यवस्थित रूप से संयोजित करने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने गति का वर्णन करने के लिए गणित का उपयोग किया, अरस्तू परंपरा के वर्णनात्मक, गैर-गणितीय दृष्टिकोण से एक कट्टरपंथी प्रस्थान। आइजैक न्यूटन ने इस संघ को गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के अपने नियमों के साथ एक नए स्तर पर ले लिया। यहां तक कि उन्हें अपने भौतिक सिद्धांतों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए नए गणितीय उपकरणों का आविष्कार करना पड़ा। संक्षेप में, गणित ने भौतिकी और भौतिकी के लिए भाषा और रूपरेखा प्रदान की, बदले में, नई गणितीय अवधारणाओं के विकास को प्रेरित किया। जबकि गणित भौतिकी से बहुत पहले अस्तित्व में था, यह भौतिक दुनिया के लिए परिष्कृत गणित का अनुप्रयोग था जिसने भौतिकी के विज्ञान को जन्म दिया जैसा कि हम आज जानते हैं।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद् स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर

15 सितंबर: इंजीनियर्स डे / मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जयंती

बांधों से विश्वविद्यालय तक: दूरदृष्टि का नाम विश्वेश्वरैया [इंजीनियर नहीं, भविष्य के शिल्पकार थे विश्वेश्वरैया]

आधुनिक भारत की प्रगति की कहानी, जो विज्ञान और तकनीक के ताने-बाने से बुनी गई है, उसमें सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का नाम एक प्रेरणादायी सितारे की तरह चमकता है। वे इंजीनियरिंग को केवल तकनीक तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि इसे राष्ट्रनिर्माण और सामाजिक उत्थान का पर्याय बनाया। उनका जीवन दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और दूरदर्शिता का समन्वय न सिर्फ़ बांध व पुल बनाता है, बल्कि समाज के लिए समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रत्येक 15 सितंबर को उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला इंजीनियर्स डे केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी प्रतिभा और सामाजिक ज़िम्मेदारी की विरासत को नमन करने का अवसर है।

1861 में कर्नाटक के मुदेनहल्ली में एक साधारण परिवार में जन्मे विश्वेश्वरैया ने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनकी असाधारण प्रतिभा ने उन्हें 1884 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी के लोक निर्माण विभाग में पहली नौकरी दिलाई, जहाँ से शुरू हुआ वह ऐतिहासिक सफर, जिसने भारतीय इंजीनियरिंग को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। उन्होंने इंजीनियरिंग को नैतिकता और राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़कर यह सिद्ध किया कि एक सच्चा इंजीनियर केवल संरचनाएँ नहीं, बल्कि समाज का टिकाऊ भविष्य रचता है।

उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है मैसूर का कृष्णराज सागर (केआरएस) बांध। 1912 से 1932 के बीच निर्मित इस बांध ने कावेरी नदी के जल को नियंत्रित कर कर्नाटक में सिंचाई और बिजली उत्पादन को नया आयाम दिया। उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए स्वचालित फ्लडगेट्स उस युग की अग्रणी तकनीक थे, जो आज भी विश्व भर के बांधों में प्रासंगिक हैं। इस बांध ने लाखों किसानों को सूखे से राहत दी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया।

विश्वेश्वरैया की दूरदृष्टि केवल बांधों तक सीमित नहीं थी। 1908 में हैदराबाद में मूसी नदी की बाढ़ से तबाह शहर को बचाने के लिए उन्होंने अभिनव जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली विकसित की, जो आज भी कारगर है। पुणे के खडकवासला बांध की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण में भी उनकी भूमिका अनुकरणीय रही। उनकी हर परियोजना तकनीकी उत्कृष्टता के साथ-साथ सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम थी। विश्वेश्वरैया का जीवन हमें सिखाता है कि इंजीनियरिंग केवल संरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज का सृजन है।

1912 में मैसूर रियासत के दीवान बनने पर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने प्रशासन और इंजीनियरिंग का ऐसा अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया, जिसने मैसूर को प्रगति के शिखर पर पहुँचाया। उनके कुशल नेतृत्व में मैसूर ने औद्योगिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में नई ऊँचाइयाँ छुईं। भद्रावती में स्थापित विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट आज भी भारत के इस्पात उद्योग की नींव है, जबकि मैसूर विश्वविद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर जैसे संस्थानों ने शिक्षा और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। उनकी दूरदर्शी नीतियों ने मैसूर को न केवल भारत का अग्रणी राज्य बनाया, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक स्थापित किया।

विश्वेश्वरैया का जीवन अनुशासन और समय प्रबंधन का जीवंत दृष्टांत था। वे अपने दिन के प्रत्येक क्षण का हिसाब रखते थे, समय की पाबंदी को सफलता का मूलमंत्र मानते हुए। उनकी यह आदत उनके कार्यों की सटीकता और दक्षता में साफ़ झलकती थी। उनका कथन, "समय और अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं," आज भी हर इंजीनियर के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उनका दृढ़ विश्वास था कि इंजीनियरिंग का उद्देश्य केवल भौतिक संरचनाएँ खड़ी करना नहीं, बल्कि समाज की ज्वलंत समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने ग्रामीण भारत में सिंचाई और जल आपूर्ति को प्राथमिकता दी, क्योंकि वे कृषि को देश की रीढ़ मानते थे। उनकी यह दूरदृष्टि आज के स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और सतत विकास जैसे अभियानों में प्रतिबिंबित होती है। वे शिक्षा के उतने ही प्रबल समर्थक थे, जितने बुनियादी ढांचे के। उनका कहना था, "ज्ञान और अनुशासन ही देश को विश्वगुरु बना सकते हैं।"

आज, जब भारत 5जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अनुसंधान में विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, विश्वेश्वरैया का योगदान हमें याद दिलाता है कि तकनीक का आधार नैतिकता और सामाजिक ज़िम्मेदारी होना चाहिए। 15 सितंबर को मनाया जाने वाला इंजीनियर्स डे हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करने और तकनीकी कौशल को पर्यावरणीय स्थिरता व सामाजिक समावेश के साथ जोड़ने का अवसर देता है।

1955 में भारत रत्न से सम्मानित विश्वेश्वरैया का सच्चा सम्मान तभी संभव है, जब हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और संसाधनों की कमी जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान तकनीक और नवाचार में निहित है। इंजीनियर्स डे हमें यह सिखाता है कि इंजीनियरिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक मिशन है—एक ऐसे भारत के निर्माण का मिशन, जो तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध हो।

विश्वेश्वरैया ने अपने जीवन का हर पल इस मिशन को समर्पित किया। यह दिन हमें आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है—क्या हम तकनीक को केवल सुविधा का साधन मान रहे हैं, या इसे समाज के उत्थान का हथियार बना रहे हैं? इस इंजीनियर्स डे पर संकल्प लें कि हम उनके आदर्शों को अपनाएँगे और भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

के. एस. सुदर्शन: हर स्वयंसेवक के हृदय में जीवित प्रेरणा

जब हृदय की धड़कनें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं-सी अनुशासित और दृढ़ हो उठती हैं, तो वे एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देती हैं। लेकिन जब ये धड़कनें अचानक थम जाती हैं, तो सन्नाटा ऐसा छाता है, मानो स्वयंसेवकों की पंक्तियाँ एक पल को निस्तब्ध हो जाएँ। 15 सितंबर 2012 की सुबह, रायपुर के आरएसएस कार्यालय में प्राणायाम करते हुए के. एस. सुदर्शन का हृदय शांत हो गया। उस सन्नाटे में एक युग का अंत हुआ। आरएसएस के पांचवें सरसंघचालक के रूप में सुदर्शन जी संगठन के मार्गदर्शक और हिंदू समाज के उन स्वप्नों व संकल्पों के प्रतीक थे, जो आज भी जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं और उनके जीवन की सादगी, विद्रोही भावना व उदारता को उजागर करते हैं। उनका जीवन राष्ट्र के गौरवमयी स्वरूप का दर्पण था, और उनकी विदाई सिखाती है कि सच्ची सेवा कभी समाप्त नहीं होती—वह युगों तक प्रेरणा देती रहती है।

कुप्पाहल्ली सीतारामय्या सुदर्शन का जन्म 18 जून 1931 को रायपुर में एक संकेटी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता-पिता कर्नाटक के मंड्या जिले के कुप्पाहल्ली गांव से थे। बचपन से ही वे जिज्ञासु और सक्रिय थे। नौ वर्ष की आयु में वे पहली बार आरएसएस शाखा में गए, जहाँ अनुशासन और खेल के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की नींव देखी। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से टेलीकॉम में गोल्ड मेडल के साथ ऑनर्स डिग्री हासिल की। उस दौर में नई पीढ़ी नौकरियों की ओर आकर्षित थी, किंतु सुदर्शन जी ने सब छोड़ 1954 में संघ का कार्य पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में स्वीकार किया। उनकी पहली जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मिली, जहाँ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार किया। वे मानते थे कि सच्ची आजादी हिंदू समाज के आत्मविश्वास से आएगी।

आरएसएस में उनका सफर सिपाही से सेनापति तक का था। 1964 में 33 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने, जो संगठन में दुर्लभ उपलब्धि थी। 1969 में अखिल भारतीय संगठन प्रमुखों के संयोजक बने। 1977 में पूर्वोत्तर भारत की जिम्मेदारी संभाली, जहाँ जातीय संघर्ष और विद्रोह की स्थिति थी। वहाँ उन्होंने स्थानीय भाषाओं में प्रवचन दिए, स्वयंसेवकों को संगठित किया और हिंदू एकता का बीज बोया। 1979 में बौद्धिक सेल के प्रमुख के रूप में संगठन की वैचारिक नींव को मजबूत किया। वे स्वदेशी, इतिहास लेखन और पर्यावरण जैसे विषयों पर चर्चाएँ आयोजित करते। 1990 में सह-महासचिव बने और 11 मार्च 2000 को सरसंघचालक। उनकी नियुक्ति अप्रत्याशित थी, क्योंकि हं. वी. शेषाद्रि प्राकृतिक उत्तराधिकारी माने जाते थे। किंतु सुदर्शन जी की संगठनात्मक क्षमता और मानव संसाधन प्रबंधन ने उन्हें चुना। स्वीकृति भाषण में उन्होंने बताया कि कैसे एम. एस. गोलवलकर ने उन्हें मध्य भारत का प्रभार सौंपा था, और गुरुजी के आशीर्वाद ने उन्हें स्वीकारने को मजबूर किया। 2009 तक, स्वास्थ्य कारणों से, उन्होंने यह दायित्व मोहन भागवत को सौंपा।

सुदर्शन जी के योगदान गहन और बहुआयामी थे। वे स्वदेशी के प्रखर पैरोकार थे। 1991 में स्वदेशी जागरण मंच के गठन के बाद वे इसके मार्गदर्शक बने। 1993 के दिल्ली अधिवेशन से स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने मत्स्य यात्रा का नेतृत्व किया, जो विदेशी ट्रॉलरों के खिलाफ तटीय भारत की यात्रा थी। नमक आंदोलन में सामान्य नमक पर प्रतिबंध के खिलाफ आवाज उठाई। वैश्वीकरण के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को निगल लेंगी। आरएसएस के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण स्वावलंबन, सतत उपभोग, वैज्ञानिक कृषि और हिंदू जीवन शैली को बढ़ावा दिया। इतिहास लेखन में उन्होंने औपनिवेशिक दृष्टिकोण को चुनौती दी। के. आर. मलकानी, देवेंद्र स्वरूप जैसे विद्वानों के साथ चर्चाएँ शुरू कीं, क्योंकि उनका मानना था कि सच्चा इतिहास राष्ट्र निर्माण का आधार बनेगा। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ पर समय रहते चेताया, जो आज राष्ट्रीय मुद्दा है। पूर्वोत्तर में उनके कार्य से कई जनजातीय समुदाय आरएसएस से जुड़े।

सुदर्शन जी का व्यक्तित्व केवल कठोरता का नहीं, बल्कि उदारता का भी था। 20 अगस्त 2012 को भोपाल में ईद के दिन वे ताजुल मस्जिद की ओर पैदल चले, नमाज पढ़ने या बधाई देने के इरादे से। स्टाफ और पुलिस ने ट्रैफिक का हवाला देकर रोका। यह खबर उर्दू अखबारों में छपी, और जमात-ए-इस्लामी हिंद के मुखपत्र 'दावत' ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। संपादक परवाज रहमानी ने लिखा कि मुसलमानों को दुख हुआ कि उन्हें रोका गया। यह उनकी हिंदुत्व की कठोर छवि के विपरीत था। वे सभी भारतीयों को हिंदू मानते थे, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। यह उनके इस्लामी विश्वासों के अध्ययन को दर्शाता था, जो 1975 की इमरजेंसी में जेल में आरएसएस और जमात कार्यकर्ताओं के करीब आने से शुरू हुआ।

उनकी सादगी भी अनुकरणीय थी। आरएसएस कार्यालयों में उन्होंने नियम बनायाः गिलास में उतना ही पानी डालो जितना पी सको। यह पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक था, जो आज जल संकट के दौर में प्रासंगिक है। वे भावुक थे, आगंतुकों से घंटों बात करते, अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएँ सुनाते। एक बार मैसूर में सुबह की सैर पर वे लापता हो गए। सात घंटे बाद राजेंद्र नगर के एक घर में मिले, जहाँ उन्होंने आराम करने की अनुमति मांगी। घरवाले टीवी पर 'मिसिंग' न्यूज देखकर हैरान थे, किंतु सुदर्शन जी ने खुद को पहचाना। डिमेंशिया की शुरुआत थी, पर उनकी स्मृति में संघ का जज्बा बरकरार था।

विवादों से वे कभी नहीं भागे। वाजपेयी सरकार की उदारीकरण नीतियों की आलोचना की, संविधान को पुराना बताया, जो राष्ट्र के मूल स्वरूप को नहीं दर्शाता। 2001 में 'स्वदेशी चर्च' की वकालत की, जो बहस का विषय बनी। ये विवाद उनके साहस को दर्शाते थे। वे शारीरिक फिटनेस पर जोर देते, प्रतिदिन योग करते। कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी में प्रवक्ता थे। एकनाथ रानाडे ने उन्हें पूर्णकालिक कार्य के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन जी ने कहा, "हिंदू समाज जल्द ही औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होकर विश्व पटल पर अपनी जगह लेगा।"

आज उनकी पुण्यतिथि पर उनकी विरासत हमें बुलाती है। वे दार्शनिक योद्धा थे, जो विचारों से लड़ते थे। नरेंद्र मोदी ने कहा, "उनका मन तीक्ष्ण, स्वभाव हास्यपूर्ण, जीवन सादा और अनुशासित था।" उनकी अनकही कहानियाँ बताती हैं कि हिंदुत्व केवल संघर्ष नहीं, समावेश भी है। स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत, अवैध घुसपैठ से सीमा सुरक्षा, इतिहास पुनर्लेखन से सांस्कृतिक पुनरुत्थान—उनके सपने आज साकार हो रहे हैं। सुदर्शन जी अमर हैं, क्योंकि वे हर उस स्वयंसेवक के हृदय में जीवित हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है। उनकी विदाई नहीं, यह नई शुरुआत है—एक ऐसे भारत की, जहाँ हिंदू गौरव विश्व गुरु बने।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

न्यायिक ढांचे में विस्तारक विकेन्द्रीयकरण जरूरी

धीतेन्द्र कुमार शर्मा

गुजरे 12 सितम्बर को राजस्थान की वकील बिरादरी में तूफानी हलचल थी। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर दोनों पीठ, राजधानी जयपुर, और कोचिंग कैपिटल कोटा, झीलों की नगरी उदयपुर के अलावा कई स्थानों पर बार एसोसिएशनों (अधिवक्ताओं के संगठन) ने तल्ख प्रदर्शनों के साथ हड़ताल (न्यायिक कार्य बहिष्कार) रखी। वजह बना केन्द्रीय कानून राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल का सोशल मीडिया पर प्रचारित एक बयान जिसमें वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के आगामी दिनों में प्रस्तावित बीकानेर दौरे के दरम्यान बीकानेर में हाईकोर्ट वर्चुअल बैंच स्थापना को लेकर कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहे हैं। वकील समुदाय इस मसले पर नाराज है और इसने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान में हाईकोर्ट की नई बैंचों की स्थापना की मांग दशकों पुरानी है। कोटा, उदयपुर और बीकानेर में इस मसले पर महीनों तक लगातार न्यायिक कार्य बहिष्कार जैसे आंदोलन हो चुके। अब भी वकील समुदाय इस मांग को लगातार माह में एक निश्चित दिन न्यायिक कार्य बहिष्कार करके इस ज्योति पुंज को प्रज्वलित किए हुए हैं। तीनों शहरों में हो रहे उग्र आंदोलन को देखते हुए दो साल पहले अगस्त 2023 में केन्द्रीय मंत्री मेघवाल ने वर्चुअल बैंच की स्थापना की घोषणा की थी लेकिन अब सिर्फ बीकानेर को लेकर दिए बयान से भेदभाव की आशंका के मद्देनजर कोटा-उदयपुर के अधिवक्ता समुदाय में उबाल आ गया। जयपुर-जोधपुर हाईकोर्ट एसोसिएशन्स अपने वकीलों का व्यवसाय प्रभावित होने के चलते ऐसी बैंचों की स्थापना का विरोध कर रहे हैं।

आइये, इनसे इतर कुछ गंभीर तथ्यों पर भी नजर डालते हैं। देश में ज्यूडिशियल पैंडेंसी ज्वलंत मुद्दा है। सत्तारूढ़ शीर्ष नेतृत्व समेत तमाम पक्ष-विपक्षी दल इस पर चिंता जताते रहते हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक सर्वोच्च न्यायलय में 88 हजार, उच्च न्यायालयों में 62 लाख और निचली अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं। इनमें तकरीबन 50 लाख मामले 10 वर्ष से अधिक वाले हैं। यही नहीं, 31.22 लाख प्रकरण वरिष्ठ नागरिकों की ओर दायर हैं जो लम्बित हैं। सर्वोच्च अदालत में पिछले माह यानी अगस्त में 7 हजार 80 नए मामले आए वहीं 5 हजार 667 का निपटान हुआ।

राजस्थान में 24.64 लाख मुकदमें लम्बित हैं। इनमें से दोनों पीठों को मिलाकर हाईकोर्ट में 6.69 लाख मामले लम्बित हैं। पिछले माह यानी अगस्त में हाईकोर्ट में 19 हजार 456 नए मामले जुड़े और 12 हजार 665 मामले निर्णीत हुए, यानी, यहां भी नए मामले जुड़ने के मुकाबले न्याय निर्णयन दो तिहाई का ही हो पाया है। नए मामलों की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत मामले ही औसतन प्रतिमाह निपट रहे हैं, यानी लम्बित न्यायिक प्रकरणों का बोझ प्रतिमाह बड़े प्रतिशत में और बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर ये हालात बेहद चिंताजनक हैं और अदालतों एवं बैंचों की संख्या बढ़ाने के विकल्प की उपेक्षा करना न्यायिक ढांचे के प्रति गिरती आस्था की गति तीव्र ही करेगा। अब रही बात कोटा, उदयपुर और बीकानेर में हाईकोर्ट बैंच स्थापना की तो इन शहरों की मांग को खारिज करना बेईमानी और ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करना ही है। देश आजाद होने से पहले स्टेट काल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर में उच्च न्यायालय थे जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के जरिये समाप्त किया गया और 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रारंभ में व्यवहारतः कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर के उच्च न्यायालय कार्य करते रहे लेकिन संविधान लागू होने के बाद 22 मई 1950 को कोटा, बीकानेर और उदयपुर की पीठों को समाप्त कर दिया गया हालांकि जयपुर पीठ ने कार्य जारी रखा। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत जोधपुर में मुख्य पीठ के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में नया उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। फिर सत्यनारायण राव, वी. विश्वनाथन और वीके गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर 1958 में व्यवहारतः कार्यरत जयपुर पीठ को भी समाप्त कर दिया गया। कालान्तर में 1976 में जयपुर में पुनः वर्तमान पीठ की स्थापना हुई। इस तरह, कोटा, उदयपुर और बीकानेर स्टेट काल से उच्च न्यायालय वाले मुख्यालय थे। राजस्थान एकीकरण में तत्कालीन राजनीतिक चुनौती से निपटने में, जोधपुर जैसे बड़े राज्य की संतुष्टि के लिए इनका बलिदान लिया गया। ऐसा बलिदान तब राष्ट्र-राजनीति के लिए बेशक अपरिहार्य और वांछनीय रहा होगा लेकिन अब गंगा में काफी पानी बह चुका। हालात 360 डिग्री बदल चुके हैं। कोटा का मजबूत राजनीतिक स्वर आज राष्ट्र की सर्वोच्च पंचायत की अध्यक्षता कर रहा है तो बीकानेर सांसद देश के कानून मंत्री है। उदयपुर का बड़ा राजनीतिक चेहरा राज्यपाल (पंजाब) जैसे संवैधानिक पद पर आसीन है। जहां तक न्यायिक ढांचे के पुनर्गठन या नए हाईकोर्ट अथवा बैंच स्थापना के कानूनी पहलुओं की बात है तो राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की सहमति से केन्द्र को प्रस्ताव भेजती है। केन्द्र सरकार के उस पर विचार करने और सकारात्मक निर्णय की दशा में राष्ट्रपति की अधिसूचना से ये अस्तित्व में आते हैं। पिछले ही माह देश के तीसरे बड़े राज्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाम्बे हाईकोर्ट की नई बैंच शुरू हुई जबकि वहां मुम्बई, पणजी, औरंगाबाद, और नागपुर में पहले से ही हाईकोर्ट की पीठें संचालित हैं। दूसरे बड़े राज्य मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर में पीठें कार्यरत हैं। छठे बड़े राज्य कर्नाटक में बैंगलूर के अलावा धारवाड़ और गुलबर्गा में हाईकोर्ट बैंच चल रही हैं।

उच्च सदन में दलितों-आदिवासियों का निम्न प्रतिनिधित्व

ओ पी सोनिक

संसद के गत मानसून सत्र में लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने 25 जुलाई को लिखित जवाब दिया कि राज्यसभा एवं विधान परिषदों में आरक्षण का काई प्रावधान नहीं है और न ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। ऐसे प्रश्न पहले भी सदन के पटल पर आ चुके हैं। जब सवालों की वजह होती है, सवाल भी तभी उठते हैं। हमारी राजसत्ताएं अक्सर ऐसे सवालों को नजरअंदाज करती रही हैं। अगर राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सांसदों की संख्या का सामाजिक परीक्षण किया जाए, तो पाएंगे कि आमतौर पर राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी के आस-पास रहा है जो दलितों एवं आदिवासियों की आबादी के अनुपात से काफी कम है। इसका मुख्य कारण है कि दलितों और आदिवासियों को राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में पहुंचाना, अधिकांश राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं रहा। हां, लोकसभा में अधिक से अधिक आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कराकर सत्ता पर काबिज होना, उनकी प्राथमिकताओं में जरूर रहा है।

देश के बड़े राजनीतिक दलों का नेतृत्व उच्च वर्ग के हाथों में रहा है। ऐसे राजनीतिक दल उच्च वर्ग के लोगों को राज्यसभा और विधान परिषदों में भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। राजनीतिक दलों ने सांगठनिक तौर पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के राजनीतिक प्रकोष्ठ या मोर्चे तो बनाए हुए हैं पर ऐसे मोर्चे राज्यसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर दबाव बनाने का साहस नहीं कर पाते। राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं में संख्याबल के आधार पर होता है। विभिन्न विधानसभाओं में आरक्षित वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टियों के अजेंडे से बंधे होते हैं। इसलिए पार्टी की विचारधारा के विपरीत जाना, उनके लिए राजनीतिक जोखिमों से भरा होता है जबकि दलितों एवं आदिवासियों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक जोखिमों से मुक्त होते हैं। इसलिए उच्च सदन में वंचित वर्गों के लोगों को भेजना दलित एवं आदिवासियों के नेतृत्व वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में शामिल होता है।

दलित नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी द्वारा राज्य सभा में भेजे गए लोगों की संख्या से इसको समझा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी ने वंचित वर्ग के लोगों को उच्च सदन में पहुंचा कर उल्लेखनीय कार्य किया है। बसपा ने राजनीतिक ताकत के दम पर अब तक करीब 30 राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया है जिनमें से करीब 50 फीसदी सांसद अकेले दलित समुदाय से रहे हैं और अभी भी बसपा के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम दलित वर्ग से हैं। देश की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समझना होगा कि जब राज्यों की विधानसभाओं में दलितों और आदिवासियों की राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो राज्यसभा और विधानपरिषदों में भी उनकी ताकत बढ़ती है और जब ताकत कम होती है तो उच्च सदन में भी ताकत सिमट जाती है। स्थाईत्व की दृष्टि से देखें तो संसद के उच्च सदन का महत्व ज्यादा होता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी उच्च सदन लोकतंत्र के मजबूत स्तम्भ की तरह खड़ा रहता है।

राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त हस्तियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान होने के कारण 250 सदस्यीय राज्यसभा को बौद्धिक सभा भी माना जाता है। उक्त प्रावधान के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सांसदों में भी दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है जबकि दलित और आदिवासी समुदाय में ऐसे अनेकों बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त अनुभवी लोग हैं, जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करके उनकी विशिष्टताओं का उपयोग लोकतंत्र के हित में किया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में सवाल-जवाब के लिए संसद से बड़ा कोई मंच नहीं होता। संसद में उठाए गए सवाल देश की जनता की आवाज माने जाते हैं। राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों की सूची के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सीधे तौर पर जुड़े प्रश्नों को लेकर उच्च सदन कितना सक्रिय रहता है।

मानसून सत्र के दौरान 21 जुलाई से 21 अगस्त तक राज्यसभा में विभिन्न सांसदों द्वारा कुल 315 तारांकित प्रश्न पूछे गए जिनमें से मात्र 1 प्रश्न और कुल 3360 अतारांकित प्रश्नों में से करीब 45 प्रश्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित पूछे गए, यानी कि देश की करीब एक चैथाई आबादी सवालों के दायरे से बाहर होती नजर आ रही है। दलितों एवं आदिवासियों से सीधे तौर पर जुड़े उक्त तारांकित प्रश्नों की संख्या आधा फीसदी से भी कम है और अतारांकित प्रश्नों की संख्या करीब एक फीसदी है। जब उच्च सदन में वंचित वर्गों के सवाल ही नहीं होंगे तो वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान कैसे निकलेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है तो उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी है। यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ समाज के लिए बनी अधिकांश नीतियां समावेशी विकास के दावे करती हैं पर दूसरी तरफ नीतियों की निर्मात्री संसद के उच्च सदन में सामाजिक समावेशन का अभाव है।

बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने सदैव वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की वकालत की। उन्होंने राजनीतिक दल बनाकर अनेकों प्रयोग किए। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा औजार बन सकती है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट में दलितों को मिला राजनीतिक आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों तक सीमित रहा जो बाद में पंचायत स्तर तक पहुंचा लेकिन राज्यसभा और विधान परिषदों की संवैधानिक संरचना ऐसी है, कि जहां आरक्षण का सीधा प्रावधान नहीं है। उक्त विधायी सदनों में प्रतिनिधित्व दलितों एवं आदिवासियों की राजनीतिक ताकत पर आधारित होता है न कि आरक्षण पर। राज्यसभा में दलितों एवं आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का सवाल केवल सांसदों की संख्या बढ़ाने का नहीं है बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सामाजिक समावेशिता एवं न्यायिकता की कसौटी भी है।

जब तक भारत में समाज के वंचित वर्गों को लोकतांत्रिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता, तब तक भारत में लोकतंत्र की अवधारणा अधूरी रहेगी। भारतीय संसद के उच्च सदन को सभी वर्गों की आवाज का मंच बनाना है तो इसके लिए दलितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं केवल नाममात्र की व्यवस्थाएं लगने लगती हैं। प्रतिनिधित्व की बात जब सदियों से दबे कुचले समाज की हो तो समावेशिता और भी जरूरी हो जाती है।

विश्व की पहली 'एआई' महिला मंत्री, उठने लगे सवाल

- हरीश शिवनानी

इस सप्ताह राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से भी छोटे देश अल्बानिया ने संसदीय इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया है जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है। यूरोप महाद्वीप के इस देश के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक 'आर्टिफ़िशियल मंत्री' 'डिएला' नियुक्त की है, जो मानव न होकर 'कृत्रिम बुद्धि जनित' यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित है। 'डिएला' का अर्थ अल्बानियाई भाषा में 'सूर्य' होता है। अल्बानिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोकरेंसी लाइसेंसिंग विभाग के प्रमुख एनियो कासो ने 12 सितंबर को अल्बानिया की राजधानी तिराना में एआई बॉट 'मंत्री' 'डिएला' का परिचय दिया। यह विश्व की एक ऐसी 'कैबिनेट मंत्री' है जो 'शारीरिक' नहीं हैं। डिएला को सार्वजनिक खरीद विभाग का मंत्री बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी निविदाओं के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज़ और पूरी तरह जवाबदेह बना कर भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करना है।

डिएला एक 'एआई-पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट' है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित किया गया था। यह ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर पहले से ही एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में कार्य कर रही थी। इसे पारंपरिक अल्बानियाई वेशभूषा में एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। इसे 'आर्टिफ़िशियल मंत्री' बनाने से अल्बानिया में संवैधानिक सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अल्बानिया के संविधान के अनुसार, मंत्रियों को 18 वर्ष से अधिक आयु का मानसिक रूप से सक्षम 'नागरिक' होना चाहिए। इस वर्ष हुए संसदीय चुनावों में रामा की सोशलिस्ट पार्टी ने 140 विधानसभा सीटों में से 83 सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता हासिल की जबकि पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साली बेरिशा के नेतृत्व वाले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन ने 50 सीटें जीतीं। बहुमत के लिहाज से सोशलिस्ट पार्टी शासन कर सकती है और ज़्यादातर कानून पारित कर सकती है, लेकिन अल्बानिया के संविधान में बदलाव के लिए उसे दो-तिहाई बहुमत यानी 93 सीटों की ज़रूरत है। अल्बानियाई राष्ट्रपति बजराम बेगज ने 13 सितंबर को रामा को नई सरकार के गठन का अधिकार सौंपा दिया। विश्लेषकों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री को एआई डिएला के निर्माण और संचालन' का अधिकार तो मिल गया है लेकिन सवाल संविधान सम्मत होने का है कि मानव की जगह 'कृत्रिम आभासी ईकाई' को मंत्री कैसे बनाया जा सकता है? स्वयं अल्बानियाई राष्ट्रपति के पास भी इसका स्पष्ट ज़वाब नहीं है। पत्रकारों के पूछे जाने पर कि क्या यह संविधान का उल्लंघन है, बेगज डिएला वाला सवाल टाल गए। अल्बानिया के प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे 'हास्यास्पद' और 'असंवैधानिक' करार दिया है। डेमोक्रेट्स के संसदीय दल के नेता गजमेंद बर्धी ने कहा कि बर्धी ने ₹प्रधानमंत्री की मसखरी को अल्बानियाई राज्य के कानूनी कृत्यों में नहीं बदला जा सकता।₹ अल्बानियाई कानूनी विशेषज्ञों ने भी संवैधानिक चुनौतियों की ओर इशारा किया है। दरअसल अल्बानिया लंबे समय से अपनी सुरक्षा और अन्य हितों के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन बेहद भ्रष्टाचार के मुद्दे के कारण उसे यह सदस्यता नहीं मिल पा रही है। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उसने एक 'गैर मानव आभासी ईकाई' पर दांव खेला है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए नवीन तकनीकी समाधानों की तलाश एक अहम पहल है लेकिन यह कई गंभीर जोखिमों और चुनौतियों से भरा हुआ कदम है। सबसे बड़ा है जवाबदेही और दायित्त्व का संकट। अगर एआई कोई गलत निर्णय लेती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है या किसी की जान को खतरा होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री एक जवाबदेह व्यक्ति होता है जिसे संसद के सामने जवाब देना होता है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। एक एआई सिस्टम को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। अगर एआई मंत्री का फैसला नागरिकों के खिलाफ जाता है, तो उस फैसले के पीछे का तर्क समझाना और उसकी समीक्षा करना असंभव हो सकता है। एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह का भी अपना जोख़मि है। एआई अपने प्रशिक्षण डेटा से सीखती है। अगर ऐतिहासिक डेटा में मानवीय पूर्वग्रह (जैसे जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव) शामिल है, तो एआई उन्हीं पूर्वाग्रहों को और मजबूत करके निर्णय लेगी। इनके अलावा एक गंभीर प्रश्न है सुरक्षा और हैकिंग का। एक एआई सिस्टम साइबर हमलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हैकर्स एआई के निर्णयों को तकनीकी चालाकी से अपने हित में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक खरीद के मामले में, हैकर्स निविदा के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए एआई में छेड़छाड़ कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मंत्री जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का हिस्सा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सबसे बड़ी है कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ। अधिकांश देशों के संविधान और कानून मंत्री पद के लिए 'मनुष्य' होने की शर्त है। एआई को मंत्री बनाना संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। यह एक अत्यंत जटिल कानूनी सवाल है, जिस पर अभी वैश्विक सहमति नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक एक उपकरण है, शासक नहीं। निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य के पास ही होनी चाहिए।

झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन योजना में का बड़ा घोटाला रामगढ़ में

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड के रामगढ़ जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की राशि में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला कल्याण विभाग के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 24 लाख 81 हजार 600 रुपए की निकासी की गई। इसको लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर चौधरी ने रामगढ़ थाने में शुक्रवार की रात प्राथमिकी दर्ज कराई है।प्राथमिकी में आपूर्तिकर्ता लातेहार जिले के अमवाटीकर निवासी स्व साकिब हुसैन के पुत्र मोहम्मद अमजद हुसैन समेत आईडीबीआई बैंक के कुछ कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 11 नवंबर 2023 को तत्कालीन डीसी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मांडू, दुलमी, गोला, पतरातू और चितरपुर प्रखंड के 358 लाभुकों का चयन शूकर पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन के लिए किया गया था। योजना के तहत लाभुकों को भुगतान के लिए तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) रामेश्वर चौधरी ने लगभग 94 लाख रुपए निकालकर आईडीबीआई बैंक रामगढ़ कैंट शाखा में जमा कराया था।रामेश्वर चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी निशा कुमारी सिंह ने एक फरवरी 2024 से 30 जुलाई 2024 तक जिला कल्याण पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाला इसी अवधि में आईडीबीआई बैंक खाते से 24.81 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। जब कल्याण विभाग ने बैंक से निकासी संबंधी दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान कराया तो हस्ताक्षर जाली पाए गए।

रजत रश्मि महाराज द्वारा नंवकार मंत्र पर आधारित जैन समाज द्वारा मृत्युंजय जप किया गया

गुरणी हेम कुवंर जी महाराज की 101 जन्म जयंती का उत्सव भी मनाया गया

अमृतसर 14 सितंबर (साहिल बेरी)

एस.एस. जैन सभा, सिविल लाइन अमृतसर के तत्वावधान में आज एक अद्वितीय एवं ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन सम्पन्न हुआ। तपाचार्या संथारा साधिका, गुरुनी माया श्री हेमकुंवर जी महाराज की 101वीं जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में तथा श्री नवकार महामंत्र पर आधारित महा मृत्युंजय जप अनुष्ठान किया गया।

सभा के उपाध्यक्ष समीर जैन ने बताया की इस दिव्य अवसर पर तपाचार्या श्री हेमकुंवर जी महाराज की सुशिष्या, उपप्रवर्तिनी महासाध्वी, दिव्य साधिका गुरुनी श्री रजत रश्मि जी महाराज (ठाणा-4) का पावन सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनके मंगल आशीर्वचन और प्रेरक उपदेशों ने सभा में उपस्थित जनमानस को आत्मशांति, संयम और धर्ममय जीवन की ओर प्रेरित किया।

गुरुनी श्री रजत रश्मि जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि नवकार महामंत्र समस्त मंत्रों का सार है, जो आत्मा को परम शांति, आत्मबल और मोक्ष का पथ दिखाता है। इस महामृत्युंजय जप अनुष्ठान से जीवन के दुःख, संकट और कष्ट दूर होते हैं तथा श्रद्धालुओं को आंतरिक शक्ति की अनुभूति होती है।

सभा में उपस्थित सभी श्रावक-श्राविकाओं ने एकस्वर में महा मृत्युंजय जप अनुष्ठान किया।महाजप कर धर्म, अहिंसा, संयम और सद्भावना का संदेश समाज तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर एस.एस. जैन सभा, सिविल लाइन अमृतसर के प्रमुख मार्गदर्शक मंगतराम राम जैन(बब्बी), पैट्रन अनिल जैन, चेयरमैन सुरिंदर जैन, प्रधान अमन जैन, महामंत्री धीरज जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष समीर जैन, उपाध्यक्ष विकास जैन (टिम्मी), उपाध्यक्ष अनीश जैन, उपाध्यक्ष विशाल जैन, कोषाध्यक्ष सौरभ जैन, मंत्री आशीष जैन, मंत्री नरेश जैन, मार्गदर्शक अरिहंत जैन, सहमंत्री विजय जैन, सहमंत्री सचिव जैन, एस एस जैन सभा गोल बाग अध्यक्ष वरिन्दर जैन आदि उपस्थित थे।

जनरेशन गैप और संवादहीनता के कारण टूटते परिवार

राजेश कुमार पासी

नानक दुखिया सब संसारा, वर्तमान हालातों पर ये बात पूरी तरह लागू होती है क्योंकि हर व्यक्ति अलग-अलग कारणों से परेशान है। आज का बड़ा सच है कि बुजुर्ग बच्चों से परेशान हैं और बच्चे बुजुर्गों से परेशान हैं। इसके लिए ज्यादातर लोग जनरेशन गैप को दोषी ठहराते हैं जबकि यह सच नहीं है। यह ठीक है कि आज की युवा पीढ़ी और पिछली पीढ़ी की सोच में बड़ा अंतर है लेकिन सोच का अंतर परेशानी का सबब इसलिए बनता है क्योंकि दोनों पीढ़ियों में संवादहीनता पैदा होती जा रही है। परिवारों का टूटना आज बड़ी समस्या बन गया है लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। हिन्दू समाज में परिवार खत्म हो रहे हैं जबकि मुस्लिम समाज इस मामले में बहुत बेहतर स्थिति में है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि दोनों समुदायों में क्या अलग है जिसके कारण एक समुदाय परिवारों के विघटन से बचा हुआ है।

मेरा मानना है कि इसकी बड़ी वजह यह हो सकती है कि हिन्दू समाज में पैसे को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि परिवार कहीं पीछे छूट जाता है। मुस्लिम समाज की सोच में इतना बड़ा अंतर नहीं आया है जितना बड़ा अंतर हिन्दू समाज की सोच में आ गया है। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हिन्दू समाज के युवा नौकरी करना चाहते हैं फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट लेकिन मुस्लिम समाज के युवा कुशलता प्राप्त करके अपना काम करने को प्राथमिकता देते हैं। जहां नौकरियों के कारण हिन्दू समाज के युवा बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज के युवा अपने ही शहरों में काम कर रहे हैं।

इसके अलावा कई और वजह हैं जिनके कारण मुस्लिम समाज की पारिवारिक संस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है लेकिन हिन्दू समाज की कमजोर पड़ गई है। परिवारों के टूटने के लिए ज्यादातर बच्चों को दोष दिया जाता है लेकिन यह सच नहीं है। परिवारों की टूटन के पीछे ज्यादातर माता-पिता ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए बदलते जमाने को दोष दिया जाता है लेकिन जमाने के साथ न बदलने वाले क्या दोषी नहीं है। 21वीं सदी की शुरूआत के बाद इतनी तेजी से सब कुछ बदला है कि उसके साथ तारतम्य बिठाना पिछली पीढ़ी के लिए मुश्किल हो गया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ युवा पीढ़ी में ही बदलाव आया है और पिछली पीढ़ी यथावत है।

जीवन का बहुत बड़ा सच यह है कि हमारे अच्छे दिनों में ही बुरे दिनों की आहट छुपी रहती है लेकिन तब हम इतने मस्त होते हैं कि उस आहट को सुन नहीं पाते। जवानी में की गई गलतियों की सजा बुढ़ापे में भुगतनी पड़ती है। अगर बच्चे बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो इसके लिए काफी हद तक हम जिम्मेदार हैं क्योंकि बच्चों को संस्कार देना आज हमारी प्राथमिकता से निकल चुका है। पैसा कमाने और घर चलाने में हम इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। आज हमारे समाज के लिए जनरेशन गैप बड़ी समस्या बन चुका है लेकिन इसकी वजह दो पीढ़ियों की सोच का अंतर नहीं बल्कि संवादहीनता है। हम इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों की भौतिक जरूरतों को पूरा करके अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लेना चाहते हैं। ऐसे में अगर हमारे बच्चे हमें अपना एटीएम समझने लगे हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए।

संवादहीनता के कारण हम बच्चों की सोच को समझ नहीं पाते हैं, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उनके साथ नहीं होते हैं। कई शहरों में बच्चियों के साथ संगठित यौन शोषण की ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पीड़िताओं की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में थी। कितनी हैरानी की बात है कि बच्चियां घुट-घुटकर जीवन बिता रही थी लेकिन माँ-बाप को पता तक नहीं था। ऐसे ही पढ़ाई के बोझ से कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली लेकिन माँ-बाप को अहसास तक नहीं हुआ। परिवारों के बीच संवादहीनता ही वो वजह है जिसके कारण माता-पिता समय पर अपने बच्चों की तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं। यह सब बताने का तात्पर्य यह है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं। अगर बच्चे शादी के बाद अलग घर बसा रहे हैं तो इसके लिए एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। एक ही घर में कई चूल्हे जलने लगे हैं इसलिए कहा जा सकता है कि एक मकान में कई घर पैदा होने लगे हैं।

बुजुर्गों की बड़ी समस्या यह है कि वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए, इसलिए वो वर्तमान हालातों से समझौता नहीं कर पाते। सब कुछ मनमर्जी का करने के चक्कर में अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जहां बच्चे वर्तमान को अच्छी तरह समझते हैं, वहीं बुजुर्गों ने जीवन के बड़े उतार-चढ़ाव देखे होते हैं इसलिए वो बच्चों को अपने तरीके चलाना चाहते हैं। बड़ी मेहनत और पूरे जीवन की जमापूंजी लगाकर बनाये गए घर भी बुजुर्गों की बड़ी समस्या है। बुजुर्गों की कोशिश होती है कि उनके घर में उनके अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। माता-पिता की यह सोच बहुत खतरनाक है कि मेरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। वो भूल जाते हैं कि बेशक उन्होंने घर बनाया है लेकिन इससे वो सबको नियंत्रित करने का अधिकार नहीं हासिल कर लेते। प्यार, ममता और मोह में बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है इसलिए हमारी भावना क्या है, हम पहचान नहीं पाते। प्यार स्वतंत्र करता है जबकि मोह बांधता है। बाप के प्यार और मोह में तो फिर भी यह अंतर पहचाना जा सकता है लेकिन माँ की ममता और मोह में तो इतना बारीक अंतर है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। माता-पिता को लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया सोचते हैं इसलिए वो बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं। विशेष तौर पर करियर और विवाह के मामले में माता-पिता बच्चों पर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। बच्चों को उनकी मर्जी की शादी से रोकने के लिए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। समाज में अपनी इज्जत का हवाला देकर जाति-धर्म के बंधनों से बाहर निकलने से रोका जाता है। विशेष रूप से माँ ऐसे मामलों में मरने की धमकी देकर बच्चों को मजबूर करती हैं। एक रिश्ते से जबरदस्ती निकाल कर दूसरे रिश्ते में जबरदस्ती बांधना कई बार परिवारों को बर्बाद कर देता है।

अपनी औकात से ज्यादा उनकी शिक्षा पर खर्च करना, बाद में इसके लिए बच्चों को ताने देना आम बात है। सवाल यह है कि क्या बच्चे ने ऐसा करने के लिए कहा था। माँ-बाप का कहना होता है कि हमने अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ऐसा किया था जबकि सच्चाई यह है कि समाज में अपनी गर्दन ऊंची रखने के चक्कर में ज्यादातर माँ-बाप ऐसा करते हैं। बच्चों को अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें बार-बार अहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हें पालपोस, पढ़ा-लिखा कर तुम पर अहसान कर रहे हैं जबकि सच यह है कि बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना एक प्राकृतिक जिम्मेदारी है। इसमें माता-पिता का एक स्वार्थ भी छिपा होता है। अगर बच्चे बोझ होते तो बिना बच्चे वाले बहुत खुश होते, क्या कारण है कि जब तक बच्चे न हो, लोग परेशान रहते हैं। हम आज्ञाकारी बच्चे चाहते हैं जबकि सच यह है कि ऐसे बच्चे बहुत कम कामयाब होते हैं। जो अपने फैसले नहीं ले पाते, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है।

दूसरों से तुलना करना गलत है लेकिन किसी वजह से असफल और बेरोजगार बच्चों के साथ बार-बार ऐसा किया जाता है। बच्चों का सबके सामने अपमान करना और दूसरों से भी करवाना, उन्हें छोटा महसूस करवाना है। कई बार रंग, कद-काठी को लेकर भी उन्हें छोटा महसूस कराया जाता है, उस पर यह जताया जाता है कि हम तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि एक उम्र के बाद बच्चों को माँ-बाप की जरूरत नहीं होती है लेकिन माँ-बाप को बच्चों की जरूरत होती है। आजकल बुजुर्गों का अकेलापन बड़ी समस्या बनता जा रहा है लेकिन इसके लिए सिर्फ बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बच्चों को अपना शहर और देश छोड़ना पड़ रहा है लेकिन कई बार स्वतंत्र रूप से जीने के लिए भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बुजुर्गों के अकेलेपन के लिए कोई भी जिम्मेदार हो लेकिन कीमत तो उन्हें ही चुकानी पड़ती है।

अगर हम चाहते हैं कि परिवार टूटने से बचे और बुजुर्गों के अकेलेपन की समस्या पर काबू पाया जाए तो दो पीढ़ियों के बीच संवाद बढ़ाने के उपाय ढूंढने होंगे। यह दुनिया का बड़ा सच है कि बातचीत से रिश्ते बनते हैं। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो भी हमें उतना ही प्यार करते हैं। सवाल यह है कि इसके बावजूद परिवार टूट रहे हैं। नई पीढ़ी को गैर-जिम्मेदार बताकर हम समस्या से दूर नहीं भाग सकते क्योंकि इससे समस्या खत्म होने वाली नहीं है। जब हम अपने बुजुर्गों से गलत व्यवहार कर रहे होते हैं तो भविष्य में अपने साथ ऐसा होने की जमीन तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चे सुनकर नहीं देखकर समझते हैं। बचपन के दिए गए संस्कार जीवन भर चलते हैं।

गायन सिखाने के लिए बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक बलात्कार किया

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर: राजधानी में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गाना सिखाने के नाम पर ओयो में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसी ही एक शर्मनाक घटना पिछले बुधवार को चंद्रशेखरपुर थाना क्षेत्र में हुई और आज प्रकाश में आई। पुलिस ने इस घटना में तीन लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। इनके नाम हैं बिरदी थाना, घिलजीखंडा गाँव, जिला जगतसिंहपुर निवासी चंदन कुमार हाथी (25), उर्फ चंदू (37), प्रसन्न कुमार आचार्य (32) और श्रीमार्ग गेस्टहाउस के केयरटेकर राजेश कुमार दास (32)। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, भुवनेश्वर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहने वाली युवती मेलोडी कार्यक्रम में गायिका के रूप में काम करती है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी चंदन से जान-पहचान हुई थी। चंदन ने बताया था कि वह एक प्रसिद्ध चैनल के स्टूडियो में संगीत से संबंधित काम करती है। कुछ दिनों तक बातचीत करने के बाद, चंदन ने युवती को संगीत रिकॉर्डिंग और फोटोशूट के बहाने चंद्रशेखरपुर थाना अंतर्गत पोखरण गाँव स्थित श्रीमार्ग गेस्टहाउस (ओयो) में बुलाया। उसने लोकेशन भेजी और युवती के कमरे के पास से गेस्टहाउस तक के लिए एक टैक्सी बुक की। बुधवार को वह दोपहर करीब 12 बजे उक्त गेस्टहाउस पहुँचा। चूँकि गेस्टहाउस एक साधारण घर जैसा था, इसलिए युवती को कुछ शक नहीं हुआ।

पूर्व योजना के अनुसार, चंदन और प्रसन्ना ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और कमरे के अंदर बारी-बारी से उसके साथ कई बार बलात्कार किया। दोपहर में जब युवती को होश आया, तो कमरा बाहर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर केयरटेकर राजेश ने दरवाजा खोला और कमरे में आ गया। राजेश ने युवती से यह भी कहा कि वह उसके साथ बलात्कार करना चाहता है। यह सुनकर चंदन और प्रसन्ना कमरे में पहुंचे तो युवती रो रही थी। बाद में, उन्होंने एक कार किराए पर ली और युवती को भेज दिया। कार चालक पीड़िता को रसूलगढ़ चौक पर छोड़कर भाग गया। उस समय, पीड़िता की सहेली ने उसे फोन किया और उसने रोते हुए पूरी बात बताई। पीड़िता की सहेली ने उसे रसूलगढ़ चौक से बचाया और उसे घर ले गई। अगले दिन, पीड़िता की बड़ी बहन ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़िता का इलाज किया गया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका बयान दर्ज किया गया। कल मुख्य आरोपी चंदन, प्रसन्ना और केयरटेकर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया।

रक्त कैंसर रोगियों के जीवन से खिलवाड़: एससीबी ने 'असिमिनीब परीक्षण' बंद किया

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर: एससीबी मेडिकल सेंटर को विश्वस्तरीय बनाने की योजना है। आने वाले दिनों में इस बड़े मेडिकल सेंटर का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवा दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से, यहाँ चल रहे एसिटिनिब के परीक्षण को रोक दिया गया है। इसलिए, अब गंभीर रक्त कैंसर के मरीज़ों को महंगी एसिटिनिब दवा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। कई मरीज़ों के लिए दो लाख रुपये की इस दवा को ख़रीदकर खाना भी संभव नहीं है। हेमेटोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुधा सेठी से घटना के बारे में पूछने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

निश्चिन्तकोइली प्रखंड के नाहंग क्षेत्र के अमीरन मोहंती नामक युवक को स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने के बाद घटना की जानकारी मिली। अमीरन के अनुसार, उनके पिता बिजय मोहंती 2001 से रक्त कैंसर से पीड़ित हैं। विजय सीएमएल और क्रोनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं। उनका कई वर्षों से एससीबी हेमेटोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा है। इसी बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 में एसीमिनिब का परीक्षण शुरू किया।

यह दवा देश के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। एसीटिनिब को केवल उन रक्त कैंसर रोगियों के लिए उपयुक्त बताया गया था जो कई दिनों से इमैटिनिब, बेसुटिनिब, निलोटिनिब, डेसाटिनिब दवाएँ ले रहे थे और उनके स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा था। विजय समेत करीब 11 मरीजों के नाम बड़ा मेडिकल कॉलेज के हेमेटोलॉजी विभाग में दर्ज थे। सभी को एसिटिनिब दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई गई। अमरन ने स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री से ट्विटर पर शिकायत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अमरन ने दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से भी संपर्क किया।

भारत सरकार को जीएसटी बदलाव के बारे में जल्दी करना चाहिए नोटिफिकेशन

अमृतसर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने 21 सितंबर को पीडीए के चुनाव में अग्रवाल को समर्थन देने की बात

अमृतसर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने अपनी नई टीम की घोषणा राणा महाजन चीफ पैटर्न

अमृतसर 14 सितंबर (साहिल बेरी)

सरकार द्वारा जीएसटी के संबंध में जो बदलाव किया है उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन ना आने के कारण व्यापारी वर्ग असमंजस में है 22 सितंबर को एक सप्ताह रह गया है इसलिए किन-किन वस्तुओं पर क्या-क्या जीएसटी होगा क्या बदलाव होगा इस बारे अभी ना तो वकीलों तथा नही व्यापारी वर्ग को इस बारे पता है इसलिए भारत सरकार को इस बारे जल्दी नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग इस जीएसटी के बदलाव के बारे में जानकारी हासिल कर सके। उक्त बात अमृतसर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की हुई आम बैठक में प्रधान मुनीष जैन ने की उन्होंने कहा कि जीएसटी पर रिफॉर्म की घोषणा तो हो चुकी है 22 सितंबर को लागू होने की बात भी की जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं हुई है सरकार को जल्द ही इस बारे निर्णय लेना चाहिए उनका संगठन सरकार से यह मांग कर रहा है कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी से किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि मॉडर्न ट्रेड के बारे में कई बार सरकार के समक्ष कई संस्थाओं ने कब आज उठाई थी लेकिन मॉडर्न ट्रेड को बंद करना सरकार के हाथ में नहीं है इसलिए यह लोगों को जागृत होना पड़ेगा कि वह मॉडर्न ट्रेड तथा ऑनलाइन के के जरिए सामान ना कर दे तथा अपने घरेलू व्यापार को प्रफुलित करने के लिए अपना जोरदार देना चाहिए पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चुनाव 21 सितंबर को जगराओं में हो रहे हैं तथा उनके संगठन के निर्णय लिया है कि एनआर अग्रवाल को समर्थन देंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए उनके संगठन द्वारा शो बेडशीट प्रभावित क्षेत्र में भेजी गई है एसोसिएशन अपने नए बने सदस्यों को सम्मानित किया गया बैठक में डिसटीब्यूटरों को कंपनियों के साथ पुरी नियमों के अनुसार कार्य करने की बात भी की गई तथा ऐसी कंपनियों से कार्य करने के लिए कहा गया जिनका बैकग्राउंड बढ़िया हो इसके अलावा बैठक में प्रधान मुनीष जैन ने नई टीम की घोषणा कि कमेटी द्वारा चैयरमेन किशन मेहरा महासचिव कौशल गंभीर चीप पैटर्न राणा महाजन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह विकी उपाध्यक्ष पूजा संयुक्त वित्तीय सचिव अविनाश शर्मा चीप पैटर्न गुरजिंदर सिंह वित सचिव संजय कपूर सचिव करण कपूर संयुक्त सचिव विजय भसीन प्रेस सचिव पवन शर्मा की टीम बनाई गई है इस अवसर पर सभी डिस्ट्रीब्यूटर शामिल थे।

कमल कोहली अमृतसर

झोने की कटाई के समय कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर एस.एम.एस. लगाना अनिवार्य : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर

सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही की जा सकेगी झोने की कटाई

अमृतसर, 14 सितंबर (साहिल बेरी)

डिप्टी कमिश्नर अमृतसर श्रीमती साक्षी साहनी के निर्देशों के तहत जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स अमृतसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) श्रीमती अमनदीप कौर की अध्यक्षता में जिले के कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेटरों और मालिकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कंबाइन मालिक झोने की कटाई से पहले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर एस.एम.एस. लगाना अनिवार्य करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना एस.एम.एस. के कंबाइन से कटाई करने वाले कंबाइन मालिकों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर श्री बलजिंदर सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि सुपर एस.एम.एस पराली को काटकर खेत में समान रूप से फैला देता है, जिससे पराली जल्दी सूखती है और गेहूं की बुवाई के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और हैपी सीडर की खेत में कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इस तकनीक से पराली को जलाए बिना ही खेत में दबा दिया जाता है, जिससे मिट्टी में मौजूद मूल्यवान पोषक तत्व, लाभदायक कीड़े और सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और मिट्टी की सेहत सुधरती है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों द्वारा पैदा किए गए हर एक दाने की खरीद के लिए वचनबद्ध है, लेकिन कटाई के समय फसल में नमी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए कंबाइन मालिकों को हिदायत दी गई कि सीजन के दौरान फसल की कटाई सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक ही की जाए।

सहायक कृषि इंजीनियर (उपकरण) श्री मनदीप सिंह ने बताया कि 25 सितम्बर 2020 के पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के आदेशों के अनुसार नियमों की अवहेलना करने वाले कंबाइन ऑपरेटरों और मालिकों पर पहली उल्लंघना के लिए 50,000 रुपये, दूसरी उल्लंघना के लिए 75,000 रुपये तथा तीसरी और उसके बाद की हर उल्लंघना के लिए 1,00,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया जाएगा।

नुआपाड़ा उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उतारेगी उम्मीदवार - प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी (उड़ीसा)

परिवहन विशेष न्यूज

भुवनेश्वर- उड़ीसा विधान सभा के अंतर्गत नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरने जा रही है 1 इसके लिए विभिन्न उम्मीदवारों से बातचीत के दौर जारी है शीघ्र ही प्रार्थी चयन कर नई दिल्ली से इसकी घोषणा की जाएगी 1 पार्टी अपने सिंबल के साथ सभी जरूरी संसाधनों सहित चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुकी है 1 यहां बीजू जनता दल आम चुनाव में यह विधानसभा सीट जीती थी और यदि भाजपा गठबंधन के अनुसार एनसीपी को सीट नहीं देती है तो एनसीपी अपने दम पर चुनाव लड़ने का कार्य करेगी व जिन उम्मीदवारों से एनसीपी की बातचीत जारी है उम्मीद है उनके खड़े होने से उड़ीसा विधानसभा में खाता खोलने की संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार) और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल (सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री-भारत सरकार) की दिशा निर्देश में उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जनता के बिच किये गए कार्यों के द्वारा बढ़ते ग्राफ के साथ आगे अपना जनाधार और भी तेजी से बढ़ाएगी व पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता स्वीकार करते हुए पार्टी के उम्मीदवार को भारी एंव व्यापक वोटों से विजयी तिलक लगाएगी 1₹- प्रदेश अध्यक्ष एनसीपी ओड़िशा डॉ राजकुमार यादव 1

करमजीत सिंह रिंटू द्वारा बाढ़ से प्रभावित 1000 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचने का कार्य किया जा रहा

अमृतसर 14 सितंबर (साहिल बेरी)

सभी वर्ग के लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए: करमजीत सिंह रिंटू

अमृतसर। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू द्वारा अपने साथियों की टीम के साथ रमदास क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा किया और राशन, चिकित्सा सामग्री, फोल्डिंग बेड, बिस्तर आदि जैसी ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराईं। अब जब गाँवों से पानी उतर गया है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ गाँवों का दौरा किया और ग्रामीणों को और किन-किन चिकित्सा सुविधाओं की ज़रूरत है, इसका आकलन किया गया था। आकलन के बाद 1000 परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया हैं। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी वर्ग के लोग जरूरतमंदों को मदद के लिए आगे आए।

इस अवसर पर करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि पंजाब और पंजाबियों पर बहुत ही बड़ी आफत आई है। इसके बावजूद सभी के हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी आफत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से प्रभावित लोगों को राहत पहचाने का भी कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि गांवो के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला प्रशासन द्वारा इस संकट की घड़ी में बाढ़ ग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गिरदावरी का भी कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि खेतों में आई रेट और मिट्टी को उठाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मशीने भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि प्रभावित लोगों को बहुत ही सहूलतो की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम द्वारा 1000 परिवारों को सभी राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य पिछले दिनों से ही शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज भी 103 परिवारों को सभी राहत सामग्री पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि घरों से पानी निकल गया है, जिससे घरों में पड़े बिस्तर बेड और कपड़े क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा क्षतिग्रस्त हुए सामान को लोगों के घरो तक लगातार पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा, रितेश शर्मा और उनकी टीम के साथी मौजूद थे।

हड़ पीड़ितों के दुख दूर करने के लिए विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री मान से जनहितैषी राजनीति का सबक सीखना चाहिए: धालीवाल

हड़ और राजनीति करने वाली पिछली सरकारों के दौर में लोग अपने ही दुखों से खुद जूझते रहे: धालीवाल

धालीवाल ने ग्राम सभाओं की बैठकों को किया संबोधित

अमृतसर/अजनाला 14 सितम्बर (साहिल बेरी)

आज विधानसभा क्षेत्र अजनाला में रावी दरिया में आई प्राकृतिक आपदा की भीषण बाढ़ के अलावा सक्की नाले और अन्य बरसाती नालों के उफान से प्रभावित गांव—चमियारी, हरड़ खुर्द, अंब कोटली, जगदेव खुर्द, कोट गुरबख्श, पच्छिया, माछीवाहला और कोटली शाह हबीब आदि में ग्राम सभाओं की बुलाई गई बैठकों को संबोधित किया गया।

बैठकों में नष्ट हुई फसलें, घर, पशु, स्कूल, धर्मशालाएं, पंचायत घर और अन्य सरकारी ढांचों को पहुंचे नुकसान की सरकारी तौर पर नियुक्त सर्वेक्षण और गिरदावरी टीमों को ईमानदारी व निष्पक्षता से सहयोग देने और निगरानी के लिए 5-5 सदस्यीय कमेटियों का गठन ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारियों और अन्य सरकारी अमले की मौजूदगी में धालीवाल की देखरेख में करवाया गया।

बैठकों को संबोधित करते हुए विधायक व पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि आज़ादी के बाद बनी कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों के विपरीत, मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली ऐसी पहली सरकार है, जिसने बाढ़ से पीड़ित लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा और सरकारी खर्चे पर प्रभावित गांवों में नदियों व नालों की गाद में दबे घरों व गांवों की सफाई के लिए जनहित में सराहनीय कदम उठाए।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में—1988, 1993, 1995 समेत समय-समय पर आई बाढ़ों के दौरान प्रभावित गांवों के लोग अपने स्तर पर ही पैसे खर्च करके गांवों की सफाई करने, मरे पशुओं को उठाने और खेतों से गाद निकालने जैसे कार्य खुद ही करने के लिए मजबूर रहे।

धालीवाल ने कहा कि फसलों के नुकसान का ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य भी आज मुख्यमंत्री श्री मान की अगुवाई में पंजाब बना है। हल्का अजनाला के 195 गांवों सहित राज्यभर के 2300 प्रभावित गांवों की सफाई के लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा 100 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए और पहले चरण में पंचायतों के खातों में एक-एक लाख रुपये भी जारी कर दिए।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री धालीवाल ने भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल और अन्य विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ लिया और कहा कि हड़ पीड़ितों की आड़ में घटिया राजनीति कर अपनी रोटियां सेंकने वाले ये दल, जिन्हें पंजाब के वोटरों ने नकार दिया है, उन्हें नकली राजनीति करने के बजाय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान और उनकी सरकार से जनहितैषी राजनीति का सबक सीखने की ज़रूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार न होती तो पीड़ित लोगों को और भी ज्यादा जानी-माली नुकसान उठाना पड़ता। क्योंकि पहले की परंपरागत पार्टियों के शासन में बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही मंत्री, विधायक और प्रशासन पीड़ितों की सुध लेने आते थे।

इस मौके पर खुशपाल सिंह धालीवाल, ब्लॉक अजनाला, रामदास और हर्षा छीना के बीडीपीओ सितारा सिंह विरक, पवन कुमार और प्रगट सिंह, ओएसडी गुरजंत सिंह सोही, पीए मुख्तार सिंह बलड़वाल सहित पंचायतों के पंच, सरपंच और गणमान्य लोग मौजूद रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023